तृतीय माला, खण्ड ११—अंक २१

सोमवार, १० दिसम्बर, १९६२
१९ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

PARLIAMENT LIBRARY
P-78
25
15-1-63

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ११ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० से १२	२०५१-६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०६३-६५
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	२०६५
तीसरी बैठक के कार्यवाही सारांश	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	२०६४
चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा सम्बन्धी स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२०६४-२१०२
श्री जवाहरलाल नेहरू	२०६४—७०, २०९३—२१०१
श्री ही० ना० मुकर्जी	२०७१-७२
श्री प्र० के० देव	२०७२-७३
श्री उ० न० ढेबर	२०७३
श्री दासप्पा	२०७३-७४
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२०७४-७५
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	२०७५-७६
श्री अ० प्र० जैन	२०७६-७७
श्री श्याम लाल सर्राफ	२०७८-७९
श्री याज्ञिक	२०७९-८०
श्री खाडिलकर	२०८०
श्री राम सेवक यादव	२०८१—८३
श्री फ्रैंक एंथनी	२०८५-८६
श्री मुत्याल राव	२०८६
श्री विद्याचरण शुक्ल	२०८६-८७
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	२०८७—८९
श्री मौर्य	२०८९-९०
श्री मु० इस्माइल	२०९०-९१
श्री विशनचन्द्र सेठ	२०९१-९२
श्री रंगा	२०९२-९३
दैनिक संक्षेपिका	२१०३-०४

लोक-सभा

सोमवार, १० दिसम्बर, १९६२

१९ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

एयर इंडिया बोइंग ७०७ विमान की दुर्घटना

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में शान्ता क्रुज़ हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग ७०७ विमान की जो दुर्घटना हुई थी, जिस के फलस्वरूप वह विमान बिल्कुल नष्ट हो गया, उसका क्या कारण था ; और

(ख) भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें फिर न हों, इस के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठा रही है, विशेष रूप से इस समय जबकि प्रत्येक उपलब्ध विमान की युद्ध प्रयत्नों के लिये आवश्यकता है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : एक कमेटी आफ़ एन्क्वायरी मुकर्रर की गई है, जिस के चेयरमैन श्री एम० एल० सोढी, डायरेक्टर आफ़ एयरोनाटिकल इन्स्पैक्शन, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, और मेम्बर श्री एम० एच० परांजपे, कंट्रोलर आफ़ एयरोनाटिकल इन्स्पेक्शन, बम्बई, हैं । वह कमेटी इस वाकये की पूरे तौर से जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट का इन्तज़ार है ।

2426 (Ai) LSD—1.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विमान की कुल कीमत कितनी थी और आग लग जाने से इस विमान की कितनी हानि हुई है ?

श्री मुहीउद्दीन : अभी तो नुक्सान का अन्दाज़ा बताना मुश्किल है। कमेटी मुकर्रर की गई है और बोइंग के इंजीनियर्ज़ वग़ैरह भी आ गये हैं, ताकि इस का अन्दाज़ा कर सकें। उस की कीमत कोई साढ़े तीन करोड़ थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभागीय तौर पर कोई प्राथमिक जांच की गयी है और यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी, नहीं। पहली जांच इस कार्य के लिये नियुक्त की गयी समिति द्वारा की जायेगी ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि दो वर्ष पहले भी एयर इण्डिया के एक सुपर कांस्टलेशन में ऐसी ही आग लग गई थी और उस समय यह पता लगा था कि सान्ताक्रुज़ हवाई अड्डे पर आग बुझाने की व्यवस्था अपर्याप्त है और सान्ताक्रुज़ हवाई अड्डे पर आग बुझाने की व्यवस्था पर्याप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक भिन्न बात है ।

†**श्री भानु प्रकाश सिंह :** जैसेकि बोइंग ७०७ का भारत में निर्माण नहीं होता है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस के केवल पुर्जे ही मंगाये जायेंगे अथवा विमान की मरम्मत के लिये विदेशी प्रविधिज्ञ भी आयेंगे और विमान को उड़ने योग्य बनाने में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बिल्कुल भिन्न बात है ।

कपड़ा मिलों में कपड़े के स्टाक का जमा हो जाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के पास कपड़े का बहुत-सा स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) कितना स्टाक है और इस के जमा हो जाने के यदि कोई कारण हों तो वे क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने साधारण स्थिति लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). देश के कुछ भागों में जैसे बम्बई शहर, पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद और अन्य क्षेत्रों में कुछ कपड़ा मिलों में कुछ कपड़ा इकट्ठा हो गया है। यह अनुमान लगाया गया है उद्योग में कुल मिला कर इस समय प्रति १५०० मीटर की ४.३ लाख गांठें हैं जो औसतन ६१/२ सप्ताह का स्टाक है ।

हाल में मिलों में जो स्टाक रहा, यह उस से कुछ अधिक है, परन्तु इस स्टाक को असामान्य नहीं कहा जा सकता। यह वर्तमान स्थिति के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता क्षेत्रों द्वारा माल का कम उठाया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार स्थिति को चिन्ताजनक नहीं समझती । भारत का रक्षित बैंक उत्पादन का स्तर बनाये रखने के लिये एक सीमा तक मिलों को वित्तीय सहायता देने को तैयार है । पूर्वोत्तर क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिये पिछले कुछ सप्ताहों में कई उपाय किये गये हैं ।

यद्यपि आपात-काल का सामना करने के लिये विश्वास और नैतिक स्तर बनाये रखने के लिये जनता, उद्योग, व्यापार और बिजनेस सभी वर्गों से उत्साहजनक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं, यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्र में उत्सुकता कम हो गई है जो इन की आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण है । सरकार देश भर में और विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यापारिक वर्ग को आश्वासन देती है कि इस स्थिति में चिन्ता करने की कोई बात नहीं है और सरकार वर्तमान राष्ट्रीय आपात-काल के दौरान उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधि बनाये रखने के लिये परिवहन और वित्तीय ऋण के बारे में सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन देती है ।

बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में स्टाक रखने की व्यवस्था किये जाने के अतिरिक्त, यदि कुछ मिलों को अपना उत्पादन बेचने में कठिनाई हो और जहां माल तेजी से न उठाया जाये, तो पृथक् पृथक् मिलों और उन की समस्याओं के अध्ययन के आधार पर बड़ा भंडार बनाने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता दी जावेगी । अतः सम्बन्धित राज्य सरकारों को व्यक्तिगत मिलों की ऐसी विशेष समस्याओं का स्थानीय श्रम और उद्योग के परामर्श से अध्ययन करने को कहा गया है और ऐसी मिलों को बड़ा भंडार बनाने और सामान्य उत्पादन जारी रखने देने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि किसी भी सूरत में उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो वे "बफ़र स्टाक" बनायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम उत्पादन बनाये रखना चाहते हैं । इस बात पर समय समय पर विचार किया जायेगा कि यह किस तरीके से किया जायेगा, बफ़र स्टाक बना कर या व्यक्तिगत मिलों को सहायता दे कर या कोई अन्य उपयुक्त उपाय करके ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं समझता हूं कि उपभोक्ता सहकारी स्टोर बनाने का निर्णय किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि उपभोक्ता सहकारी स्टोर स्थापित करने के मामले में कितनी प्रगति की गई है और क्या ये उपभोक्ता सहकारी स्टोर एक ओर तो माल उठाने और मिलों को राहत देने में और दूसरी ओर सभी स्तर पर समय पर संभरण का आश्वासन देने में सहायक होंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संभरण बनाये रखने में कोई कठिनाई नहीं है । जहां तक उपभोक्ता सहकारी स्टोर स्थापित करने का सम्बन्ध है, इस मामले में कई कदम उठाये गये हैं और इस कार्य में शीघ्रता की जा रही है । इन स्टोरों से सस्ते मूल्य पर, भली प्रकार वितरण में सहायता मिलेगी । परन्तु वास्तविक प्रश्न यह है कि जहां तक उत्पादन बनाये रखने का प्रश्न है, सम्बन्धित मिलों की सहायता करने के लिये प्रत्येक कदम उठाया जा रहा है ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या सरकार ने मूल्य कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है और क्या कुछ स्थानों पर रुई के स्टाक कम करने के लिये मूल्य में कमी नहीं की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । अधिकतम मल्य छपे हुए मूल्य हैं । मिलें, अधिकतम मूल्य के भीतर, स्थानीय मूल्य निर्धारित कर सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को आपात काल में सेना में लड़ाकुओं या प्रशिक्षकों अथवा किसी अन्य रूप में काम पर लगाने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप और ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). पहले सैनिक-सेवा किये हुए भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक दोबारा सेवा में आने या सेना में भरती होने के उसी प्रकार अधिकारी हैं जिस प्रकार कि सेना भूतपूर्व सैनिक। इस प्रकार उनमें निम्न योग्यतायें होनी चाहियें :—

(१) मेडिकल श्रेणी 'ए',

(२) ऊंचाई, वजन और सीने की निर्धारित नापें, जो नए रंगरूटों के लिए निश्चित की गई हैं। इन नापों में वर्तमान आपत-काल में किसी हद तक छूट दी गई है ; और

(३) निम्नलिखित आयु-सीमा के अन्तर्गत होना :—

(१) जूनियर कमीशंड अफसर .	४८ वर्ष
(२) अदर रैंक्स .	४५ वर्ष
(३) नान-काम्बैटैन्ट्स (इनरोल्ड) .	५० वर्ष

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी संस्थाओं अथवा अपने प्रतिनिधियों के जरिये इस मामले में सरकार को अभ्यावेदन किया है कि संकट की इस घड़ी में उनकी सेवायें काम में लायी जायें और यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने राजधानी में भूतपूर्व आज़ाद हिन्द सेना संस्था से अथवा असैनिक रोजगार में लगे उनके प्रतिनिधियों से सम्पर्क करने का कोई प्रयत्न किया है ताकि कोहिमा और इम्फाल के व्यक्तियों की, जो रूढ़िवादी लड़ाई में ही नहीं अपितु गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण का काम कर सकते हैं, सेवायें प्राप्त की जा सकें जिसकी कि इस समय बड़ी आवश्यकता है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : सम्पर्क रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भर्ती हो सकते है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। वह मेरी बात सुनें। प्रश्न यह था कि क्या कोई सम्पर्क किया गया है। इसका उत्तर है कि सम्पर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान भूतपूर्व आज़ाद हिन्द सेना संस्था के मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि आज़ाद हिन्द सेना के २०००० भूतपूर्व सैनिक सेना में काम करना चाहते है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : जैसा मैं बता चुका हूं, वे भर्ती हो सकते हैं। यदि उन्हें उपयुक्त समझा गया, तो उनको भर्ती कर लिया जायेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार को कुछ ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज में कार्य करने वाले सिपाहियों अथवा सेनापतियों को जो प्रतिरक्षा के लिए दूसरी और तीसरी पंक्तियां तैयार की जारही हैं उनके लिए उनकी सेवायें प्राप्त की जाएं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जो यह दूसरी, और तीसरी लाइन आफ डिफेंस है इसके लिए उनको भरती करने के लिए क्या सरकार कोई तजवीज कर रही है ताकि उनको वहां इस्तेमाल किया जाए ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : वह विचाराधीन है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि आई० एन० ए० के भाइयों का जो ८५ लाख के करीब पेंशन का रुपया वाजिब है उसको सरकार देने की कोई तजवीज कर रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह अलाहिदा बात है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या सरकार ने आज़ाद हिन्द सेना के उन प्रतिष्ठित सदस्यों से बातचीत की है, जो सरकार के सदस्य है और इस मामले में उनके विचार जाने हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : निश्चय ही हम उस माननीय मित्र से परामर्श करेंगे जो सरकार का भी सदस्य है। हम ऐसा करते रहेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : औचित्य प्रश्न पर। सरकार ने भूतपूर्व जनरलों और हमारी भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों से सम्पर्क बनाया है। सरकार इस संकट-काल में नेता जी की फौज के सदस्यों से कोई सम्पर्क कायम रखना आवश्यक नहीं समझती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उस नियम को बतायें जिसका उल्लंघन किया गया है जिस पर मैं औचित्य प्रश्न का निर्णय दूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : फिर यह स्पष्टीकरण के हेतु हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गयें पत्र

प्रागा टूल्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन—उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटड, सिकन्दराबाद की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ६४०/६२]

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: मैं भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६२ (भाग २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ६४१/६२]**

कपड़ा मशीनरी (उत्पादन तथा वितरण) नियन्त्रण आदेश

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३२१९ में प्रकाशित कपड़ा मशीनरी (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ६४२/६२]**

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

तीसरी बैठक के कार्यवाही-सारांश

†**श्री मानसिंह पु० पटेल (मेहसाना)**: मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की तीसरे अधिवेशन में हुई तीसरी बैठक के कार्यवाही—सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव: मैं ३ दिसम्बर, १९६२ को सभा को दी गयी अन्तिम रिपोर्ट के बाद चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(१) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) बिल, १९६२ ।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) बिल, १९६२ ।

चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण से उत्पन्न सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु-शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा सम्बन्धी स्थिति पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

एक महीना हुआ, ८ नवम्बर को, मैंने चीन द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप आपात की उद्घोषणा के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात् एक अन्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया गया था कि चीन ने किस प्रकार भारत की मित्रता और सद्भावना का और पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। सभा ने सर्व सम्मति से संकल्प पास किया था कि जिसमें भारत की जनता का अपनी पवित्र भूमि से आक्रमणकारियों को खदेड़ देने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की गयी थी, चाहे वह संघर्ष कितना ही लम्बा और कड़ा हो। इस संकल्प पर काफी चर्चा हुई थी और इसमें बहुत सदस्यों ने भाग लिया था। १४ नवम्बर को यह संकल्प सर्व सम्मति से ही नहीं बल्कि एक असामान्य ढंग से पास किया गया था जिसमें सदस्यों ने खड़े होकर आक्रमणकारियों को खदेड़ने का वचन लिया था। हम उस वचन पर दृढ़ हैं।

दो या तीन दिन बाद चीनी सेनाओं ने हमारी सेनाओं पर सेला और वालोंग में वड़ा आक्रमण कर दिया। इससे हमारी सेना को, १८ नवम्बर को, सेला और वालोंग से और कुछ समय बाद बोमडिला से पीछे हटना पड़ा।

२१ नवम्बर को चीन सरकार ने २१–२२ नवम्बर की अर्ध-रात्रि से युद्ध विराम और १ दिसम्बर से अपनी सेनायें पीछे हटा लेने की एक पक्षीय घोषणा की थी। २३ ता० को हमने कुछ स्पष्टीकरण मांगा और २६ ता० को हमें इसका उत्तर मिल गया। ३० ता० को हमने फिर स्पष्टीकरण मांगा।

२२ नवम्बर को लंका सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने कोलम्बो में छः तटस्थ देशों का एक सम्मेलन बुलाया है। बाद में इसकी तिथि में परिवर्तन कर दिया गया और आज यह कोलम्बो में शुरू हो रहा है।

२८ नवम्बर को चीन के प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई का एक पत्र मिला जिसमें भारत के प्रधान मंत्री से युद्ध-विराम के चीनी प्रस्ताव को मान लेने का अनुरोध किया गया। मैंने १ दिसम्बर को इसका उत्तर भेज दिया। ये पत्र वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गयी "युद्ध और शान्ति में चीनी आक्रमण" पुस्तिका में प्रकाशित कुछ नक्शों समेत दिये गये हैं।

युद्ध-विराम तो हुआ परन्तु चीनियों ने पहले कुछ दिनों में उसका अनेक बार उल्लंघन किया। यह स्पष्ट नहीं है कि चीनी सेनायें कहां तक पीछे हटी हैं। कुछ हद तक वे हट गयी हैं परन्तु अभी भी बहुत सी चीनी सेनायें आगे के क्षेत्रों में मौजूद हैं।

५ दिसम्बर को चीनी 'रेडक्रास' ने भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को बोमडिला में ६४ घायल और बीमार युद्ध बन्दियों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में वे औ घायल बन्दियों को हमें सौंप देंगे।

२० अक्तूबर को हुए चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद चीनियों ने एक त्रि-सूत्री प्रस्ताव रखा था जिसमें युद्ध-विराम और अपनी सेनायें हटा लेने का, यदि भारत इन प्रस्तावों से सहमत हो, प्रस्ताव किया गया था अन्यथा युद्ध फिर छिड़ सकता है। २२ अक्तूबर को हमने उत्तर दिया कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मान सकते और हमारा ८ सितम्बर के पहले की स्थिति कायम करने का प्रस्ताव साधारण और सीधा है। युद्ध विराम और अपनी सेनायें पीछे हटाने का २१ नवम्बर, के चीनी प्रस्ताव में केवल २४ अक्तूबर के प्रस्ताव को दोहराया गया है और इसमें युद्ध-विराम और अपनी सेनायें पीछे हटाने की एकपक्षीय घोषणा की गयी है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने १ दिसम्बर को प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई को पत्र लिखा जिसमें उन्हें बताया कि चीनियों का त्रिसूत्रीय प्रस्ताव स्वयं उनके अपने सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है जिनका वे अपने संलेखों एवं पत्र-व्यवहार में प्रतिपादन करते रहे हैं। हम इस पर सहमत नहीं हो सकते और न ही हम आक्रामक को ८ सितम्बर, १९६२ के बाद आक्रमण द्वारा प्राप्त की गयी स्थिति पर कायम रहने देना चाहते हैं क्योंकि इससे यही नहीं होगा कि जो कुछ उसने हथिया लिया है, वह दे दिया जाय परन्तु उससे भविष्य में भी हमारे देश पर आक्रमण का खतरा बना रहेगा।

इस पत्र का प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई से कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं आया है। परन्तु कल "पेकिंग रेडियो" ने एक लम्बा वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें हमारे प्रस्ताव को ठुकरा कर यह कहा गया था कि उन्होंने हमारे पेकिंग स्थित स्थानापन्न राजदूत को एक नोट दिया है जिसमें भारत सरकार से तीन प्रश्न पूछे गये हैं। ये प्रश्न हैं (१) भारत सरकार युद्ध-विराम से सहमत है या नहीं ? (२) भारत सरकार इस बात से सहमत है या नहीं कि दोनों ओर की सेनायें ७ नवम्बर, १९५९ की वास्तविक नियंत्रण रेखा से २०–२० किलोमीटर पीछे हट जायें, और (३) क्या भारत सरकार इस बात से सहमत है या नहीं है कि एक असैनिकीकृत क्षेत्र बनाने के लिये दोनों पक्षों की सेनाओं को पीछे हटाने, चौकियां स्थापित करने और बन्दी सैनिकों को लौटाने के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये दोनों पक्षों के अधिकारियों की बैठक हों ?

इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं सदन को इन आक्रमणों के बारे में पूर्व इतिहास बतलाता हूं। ८ सितम्बर, १९६२ से पूर्व छोटे सीमान्त गांव, लोंगजू को छोड़कर चीनियों द्वारा नेफा क्षेत्र में कोई कार्यकारी आक्रमण नहीं किया गया था। आक्रमण ही नहीं बल्कि पहले बार बार यह आश्वासन दिये गये थे कि चीनी तथा-कथित मैकमोहन रेखा को पार नहीं करेंगे और यद्यपि वे इस रेखा को ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गयी अवैध रेखा मानते हैं, वे इस रेखा को बर्मा में रेखा मानते रहेंगे। अतः ८ सितम्बर, १९६२ को छागला दर्रे के निकट इस रेखा के पार आक्रमण कर इन आश्वासनों का उल्लंघन ही नहीं किया परन्तु इतिहास में प्रथम बार उस सीमा का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया है।

यह मामला साम्राज्यवादी अतिक्रमण एवं विस्तार का है। चीनी सेनायें बड़ी संख्या में सीमा को पार करती रहीं और २० अक्तूबर, १९६२ को उन्होंने भारतीय क्षेत्र में भीषण आक्रमण कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चीनी आक्रमण के पांच वर्ष पुराने इतिहास में, प्रथम बार यह भारी आक्रमण किया गया और भारतीय क्षेत्र पर नियमित रूप से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। उसी दिन लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में उसी प्रकार का आक्रमण हुआ। यह स्पष्ट था कि यह हमारे सीमान्त के विभिन्न भागों पर एक सम्मिलित हमला था। उसके शीघ्र बाद अर्थात् २४ अक्तूबर को चीनियों ने अपना त्रिसूत्रीय प्रस्ताव किया, जो कि यदि मान लिया जाता, तो उन की स्थिति और भी मजबूत हो जाती और वे भविष्य में और भी आक्रमण कर सकते। हम इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे, इस लिए इसे अस्वीकार किया गया।

मैं यह दुहराना चाहता हूं कि इन आक्रमणों को, जो कि २० अक्तूबर को बड़े पैमाने पर शुरू हो गये थे, साम्राज्यवादी आक्रमण ही कहा जा सकता है। यह नोट करना चाहिये कि चीनी सरकार ने जो प्रायः अपने आप को साम्राज्यवाद का विरोधी कहती है, स्वयं एक बड़ा साम्राज्यवादी हमला

किया है । यह ,बात बहुत संगत है कि चीनी हमले नेफा क्षेत्र में कभी दाखिल नहीं हुए । एक क्षण के लिये उनके दावे की सचाई को एक ओर रखा जाये । उन के कहने के अनुसार, मैकमाहन लाइन ५० वर्ष पहले बनाई गई थी । यह लाइन मैकमोहन ने नहीं खींची थी, बल्कि एक पुरानी बात को स्वीकार किया गया था अर्थात् जल विभाजन को सीमान्त माना गया था । उस समय से और वास्तव में उस से बहुत पूर्व, यह स्पष्ट है कि चीनी वहां नहीं थे ।

आजादी के बाद हम ने नेफा क्षेत्र को विकसित करने का प्रयत्न किया है और स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाये हैं । सहसा चीनियों ने आक्रमण कर के हमारे सीमांत को भंग किया । क्या यह शांति पूर्ण तरीके से समझौता करने का तरीका है ? मैं फिर दोहराता हूं कि चाहे दावे कुछ भी हों,यह तैयारी किया हुआ आक्रमण चीनी दावों के विरुद्ध है और इसे साम्राज्यवादी प्रसारवाद और आक्रमण कहा जा सकता है ।

इसके उत्तर में हमने कहा था कि हम कोई बात चीत नहीं कर सकते जब तक कि आक्रमण खत्म न किया जाये और नेफा और लद्दाख दोनों स्थानों पर ८ सितम्बर, १९६२ से पहले वाली स्थिति को कायम न किया जाय । पिछले कुछ महीनों में हम ने निरन्तर यही स्थिति अपनाई है । शांति के लिये उत्सुक होते हुए हमने यह कम से कम शर्त रखी । उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है । इसके परिणामस्वरुप अब आपसी बात चीत का कोई आधार नहीं है । इसके बार बार शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर दिया है । किन्तु जब तक आक्रमण जारी है, और हमें इसे तथ्य मानने के लिए कहा जाता है ऐसा नहीं हो सकता चीनी सरकार की ओर से जो तीन प्रश्न पूछे गये थे, उन में से पहला यह था कि हम युद्ध-विराम को मानते हैं या नहीं मानते । चीन सरकार की घोषणा एक पक्षीय थी किन्तु इसे हमने स्वीकार कर लिया था और हमने इस को भंग करने के लिये कुछ नहीं किया ।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम यह मानते हैं या नहीं कि दोनों पक्षों के सशस्त्र दल अलग हो जायें और नवम्बर, १९५९ की वास्तविक नियन्त्रण की रेखा से २० किलोमीटर की दूरी तक हट जायें । हम एक समझौते द्वारा किये गये प्रबन्ध के अनुसार दोनों पक्षों के शस्त्राशस्त्र दलों के अलग हो जाने के हक में हैं । किन्तु यह प्रबन्ध केवल इस आधार पर हो सकता है कि ८ सितम्बर, १९६२ को चीन सरकार ने जो और अतिक्रमण किया था, उसे बन्द किया जाये । यदि चीनी सरकार का कहना है कि यह भारतीय राज्य क्षेत्र नहीं था । तो इसका अदालती निर्णय किया जा सकता है । तथापि तथ्य यह है कि यह बहुत समय से भारतीय कब्जे में है और इस को भुलाया नहीं जा सकता । भारत सरकार ने अपनी ओर से बता दिया है कि नवम्बर, ७,१९५९ की तथाकथित वास्तविक नियन्त्रण रेखा क्या थी । वह चीनी निर्वाचन से सहमत नहीं है, जोकि वास्तविक तथ्यों के अनुसार नहीं है। पिछले पांच वर्षों में दो सरकारों के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है, उस से तथ्यों को आसानी से पता लगाया जा सकता है । चीन सरकार हम से यह आशा नहीं कर सकती कि हम नवम्बर, ७,१९५९ की वास्तविक नियन्त्रण को तथा कथित रेखा को मान लें, जो कि स्पष्टतया तथ्यों के अनुसार नहीं है । हम ने जो सुझाव दिया था वह सीधा और साधारण प्रस्ताव था और वह यह था कि ८ सितम्बर,१९६२ से पहले वाली स्थिति को बहाल किया जाये, जब कि अगला आक्रमण शुरू किया गया था । यह स्पष्टतया वास्तविक है और इस सिद्धांत पर आधारित है कि शांतिपूर्ण समझौते से पहले आक्रमण को खत्म किया जाये । प्रधान मंत्री चू० एन० लाई के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ है उस में इस मामले को उठाया गया है । मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य इसे पढ़ चुके हैं ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तीसरा प्रश्न यह है : क्या भारत सरकार सहमत है या नहीं कि दोनों देशों के अधिकारी आपस में मिलें और दोनों पक्षों के सशस्त्र दलों के पीछे हटने सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करें, ताकि ऐसा क्षेत्र बनाया जा सके जिसमें सेनायें न हों ? यह स्पष्ट है कि यदि अधिकारियों ने भेंट करनी है, तो उन्हें युद्ध विराम और पीछे हटने के प्रबन्धों के बारे में, जिन्हें क्रियान्वित किया जाना है, स्पष्ट और ठीक ठीक निदेश होने चाहियें । जब तक उन्हें ऐसी हिदायतें न मिलें, जो कि भारत और चीन के बीच समझौते के आधार पर होगी, वे काम नहीं कर सकेंगे । इस लिये इस बात का पहले फैसला किया जाना है कि कौन सी रेखा को क्रियान्वित किया जाना है । ८ सितम्बर, १९६२ से तुरन्त पूर्व की वास्तविक नियन्त्रण रेखा और चीन द्वारा बताई गई ७ नवम्बर, १९५९ की रेखा के बीच लगभग २५,०० वर्ग मील भारतीय राज्य क्षेत्र का अन्तर है, जिसे चीन ने पिछले तीन महीनों में बड़े पैमाने पर आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया था । चीनी सरकार ने अपनी तरफ से रेखा की व्याख्या करके आक्रमण से होने वाले लाभों को पक्का करना चाहती है ।

कोई व्यक्ति जो पिछले कुछ वर्षों का इतिहास पढ़े, खासकर पिछले कुछ महीनों का, इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि विभिन्न लाइनों का चीनी निर्वाचन परिस्थितियों के साथ बलदता रहता है और वे उस लाइन को मानते हैं जो उनके लिये लाभदायक हो । कभी कभी वे किसी लाइन के भाग को स्वीकार करते हैं, शेष नहीं जो कि उन के लिये लाभदायक नहीं होती । पिछले पांच वर्षों में जो कुछ हुआ है और जिस प्रकार परिस्थितियां बदलती रही हैं, उन की चर्चा करना आसान नहीं है । फिर भी मुख्य तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है । चीन के चाहे कुछ भी दावे क्यों न हों, कोई भी अस्थायी व्यवस्था इन तथ्यों के आधार पर ही हो सकती है । यह आधार चीन द्वारा बताई जाने वाली वास्तविक नियन्त्रण की रेखा नहीं हो सकता । यह रेखा तो बराबर बदलती रही है ।

इन परिस्थितियों और चर्चाओं के प्रति चीन की ओर से अजीब सनकीपन और चालाकी बरती गई है, निस्सन्देह सभा को यह बात मालूम है । वे हम पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाते हैं । उनकी मति में हम अपनी ही भूमि पर आक्रमण करेंगे तथा वे वहां हमारी भूमि पर उसकी रक्षा के लिये आयेंगे । जहां तक मुझे इतिहास की जानकारी है वे उस स्थान तक आ गये हैं जहां वे पहले कभी नहीं थे । वे साम्राज्यवादिता के विरुद्ध शिक्षा देते हैं और स्वयं वे उसी पुरानी साम्राज्य वादिता तथा प्रसारवादी नीति का आश्रय ले रहे हैं । उनकी नीति निर्लज्ज युद्धलोलुपता की है । उनका कहना है कि भारतीय सेनाओं ने सीमान्तवर्ती गार्डों पर आक्रमण किया है और उन्होंने आत्मरक्षात्मक कार्यवाही की है । यह विचित्र बात है कि आत्मरक्षा करते हुये उन्होंने भारतीय प्रदेश पर २०,००० वर्ग मील तक अधिकार कर लिया है । यह सारी कार्यवाही स्पष्टत: अन्यायपूर्ण है ; अनुचित और गलत है । यह शब्दों का दुरुपयोग है । जो लोग दोहरी भाषा का प्रयोग करते हैं ; जितनी कथनी और करनी में इतनी विषमता है उनसे किसी बात पर निबटना कठिन है । मुझे यह कहते हुए खेद है कि चीनी सरकार के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

चीन की भारत को धमकी काफी लम्बे अरसे तक रहेगी और पिछले पांच वर्ष और इसमें भी गत तीन महीने पहले की गतिविधि से चीन की मूलत: प्रसारवादी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है ।

सारा संसार जानता है कि हम शांतिप्रिय हैं और हमने सदैव शांति प्रिय तरीकों से काम करने का प्रयत्न किया है। स्वैच्छा से हम इन युद्ध सरीखे कामों में संलग्न नहीं हुये हैं भारत माता की रक्षा प्रत्येक भारतीय का प्रधान कर्तव्य है। सामाज्यवादी और विस्तारवादी चुनौती केवल हमें ही नहीं परन्तु सारे विश्व को चुनौती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और परम्परा का खुले आम उल्लंघन है। यदि आज हम इस आक्रमण को सहन कर चुप बैठे रहते हैं तो यह भय भारत को ही नहीं परन्तु एशिया के सब देशों के लिये बना रहेगा। यह विश्व के लिये गलत शुरुआत होगी। अतः हम पूर्ण प्रयत्न कर पूरी योग्यता के साथ इस चुनौती का सामना कर जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। किन्तु इसके साथ ही हम सदा शांतिपूर्ण तरीकों से इस विवाद को हल करने का प्रयत्न करेंगे किन्तु शांतिपूर्ण हल के लिये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने पर ही कुछ परिणाम निकल सकता है।

चीन की कार्यवाही विश्व चेतना का अपमान है। जिन अनेक देशों से हमें सहानुभूति परक समाचार मिले हैं उनसे यह स्पष्ट है। अब भी हम आशा करते हैं कि हमारे शांतिपूर्ण और औचित्य-युक्त दृष्टिकोण से वे सहमत हो जायेंगे।

अन्यथा यह संघर्ष बढ़ सकता है और इससे व्यापक रूप में संकट हो सकता है। यह संकट भारत और चीन को ही नहीं है सारे जगत को है। अगर उन्होंने हमारी प्राथमिक बातें मान लीं तो इन विवादों को हल करने के लिये हम शांतिपूर्ण, ढंग से इस पर विचार कर सकते हैं।

हमने चीन की सरकार अथवा चीन के प्रधान मंत्री के समक्ष कई बार इस बात को दोहराया है हमें इस विवाद को हल करने के लिये शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ; परस्पर मुलाकात के अतिरिक्त ही अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से इस समस्या के प्रति विचार करना चाहिये उचित समय आने पर और संसद का अनुमोदन प्राप्त होने पर मैं इस बात के लिये भी सहमत हूं कि यह सीमा सम्बन्धी विवाद हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को निदिष्ट कर दी जाय मेरा निवेदन है कि इससे अधिक युक्ति संगत और सचित और दृष्टिकोण नहीं हो सकता। किन्तु यह सभी हो सकता है जब आक्रान्ता अधिकृत स्थान खाली कर दे और ८ सितम्बर, १९६२ से पूर्व की स्थिति उत्पन्न हो जाय। आज कोलम्बो सम्मेलन हो रहा है। इसमें भारत और चीन के मत भेद दूर करने के लिये दोनों पक्षों को मान्य सिफारिशों पर विचार किया जायगा हम उनकी मैत्री पूर्ण भावना का स्वागत करते हैं। हम इस संकट की स्थिति दूर करने के लिये उनके प्रयत्नों की सराहना करते हैं। मुझे विश्वास हैं कि एक आक्रमणकारी और प्रसारवादी सत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता। और आक्रमण के फलस्वरूप अधिकार की गयी भूमि को दोनों पक्षों द्वारा इस विवाद को हल करने से पहले खाली करना आवश्यक है।

पर्याप्त समय से हम तटस्थ नीति में विश्वास करते रहे हैं मेरा विश्वास है कि ये सही नीति है। इस नीति से हमारा अभिप्राय है कि किसी सैनिक गुप्त अथवा सैनिक प्रयोजन के लिय किसी का साथ नहीं देना। मेरा विचार में यह नीति जारी रहनी चाहिये। किन्तु हमें अपनी मातृभूमि की रक्षाके लिये सब संभव उपाय उठाने चाहिये और इस पवित्र कार्य में सहायता के लिय इच्छुक सभी मित्र देशों से हमें सहायता स्वीकार कर लेनी चाहियें।

इस संकट के समय जिन देशों ने हमारा साथ दिया है हमारे प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है कि वे देश के इस विचार धारा से सहमत होंगे कि हमारे लिये तटस्थ नीति

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का परित्याग न करना उचित है। केवल एक ही ऐसा देश है जो तटस्थता की नीति का अनुमोदन नहीं करता है और वह देश चीन है उनका विचार है कि परिस्थितियां हमें इस नीति को छोड़ने के लिये मजबूर कर देंगी और हमने इसको छोड़ दिया। अतः यह स्पष्ट है कि और स्वयं माननीय सदस्य इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि इस दिशा में चीन का दृष्टिकोण न केवल हमसे किन्तु विश्व के सभी देशों से भिन्न है।

इस विषय में हम अत्यन्त गम्भीर हैं किन्तु मैं अत्यन्त संयत भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसमें अन्तर्गस्त विवाद अत्यन्त गम्भीर है और उन्हें आसानी से या एक दूसरे की निन्दा द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। यह देश के भविष्य का प्रश्न है। इन विशाल समस्याओं का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस समस्या के कई पहलू हैं सैनिक, आर्थिक और एशिया के बड़े बड़े देशों के साथ हमारे सम्बन्ध तथा विश्व शान्ति का भविष्य। यद्यपि हम इन समस्याओं के प्रति अत्यन्त भावुकतामय ढंग से विचार करते हैं किन्तु हमें भावनाओं में प्रभावित होकर गलत काम नहीं करना चाहिए हमारा भविष्य कठिनाइयों से पूर्ण है और इस का सामना करने के लिए देशवासियों को कठिबद्ध हो जाना चाहिये। हमें हर तरह से अपने आप को सशक्त बनाना है और देश में उचित वातावरण बनाना है। हम इस के लिए प्रयत्नशील हैं।

यद्यपि आजकल यथार्थ युद्ध नहीं हो रहा है, किन्तु संकट की स्थिति और भय यथावत् बना हुआ है और जब तक चीन की वर्तमान नीति और उसके सैनिक कारनामें जारी हैं, यह हमारी स्वतंत्रता और एकता के लिए चुनौती है। अतः हमें पूरी ताकत के साथ इस धमकी का मुकाबला करना है। अन्त में हमारी विजय होगी और शान्ति का पक्ष मज़बूत बनेगा।

२० अक्तूबर को चीन द्वारा आक्रमण करने के पश्चात् संघर्ष अथवा युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका भावी रूप कुछ भी क्यों न हो, किन्तु यह असंदिग्ध है कि यह स्थिति पर्याप्त समय तक रहेगी। यह पांच वर्ष या उससे अधिक तक भी रह सकती है। हमें या सब देश को यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि इसके लिए विशाल प्रयत्न की आवश्यकता है। मैं यह बात पूर्ण उत्तरदायित्व और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अन्त में विजय हमारी होगी किन्तु इसके लिए अथक प्रयत्न और असीमित त्याग की आवश्यकता है। हमें चीन के साम्राज्यवादी हथकंडों के सामने नहीं झुकना। हमें यह बात याद रखना है कि हम युद्ध के लिए युद्ध नहीं किन्तु देश की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता की रक्षा, भारत में स्वतंत्र समाज की रक्षा और विश्व में शान्ति का प्रश्न है और वस्तुतः यह बड़े दुख की बात होगी कि यदि हम देश की रक्षा के प्रयत्न में कहीं कोई ऐसा काम न कर बैठें कि जो इस समस्या को एक डरावना युद्ध का रूप न दे दे। हमें यह बात सदा याद रखनी है। किन्तु इस समय हमारे सामने सब से महत्वपूर्ण प्रश्न देश की स्वतंत्रता की रक्षा का है जिसे हम ने गहन कठिनाइयों और त्याग के बाद प्राप्त किया। १४ नवम्बर को पारित किये गये संकल्प में सभा ने यह बात भली प्रकार व्यक्त कर दी है कि वह देश रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। हम अब भी उस संकट के प्रति पूर्ण स्थिर और आशावान हैं और मुझे विश्वास है कि इस का पूर्ण पालन करने में सफल होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा सम्बन्धी स्थिति पर विचार करने के पश्चात् सरकार इसका मुकाबला करने के लिए अपनाये गये उपायों और नीति का अनुमोदन करती है ।"

†**श्री अ० सि० सहगल** (जंजगीर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : मुझे विश्वास है कि आज सदन इस अवसर का स्वागत करता है जब कि वह १४ नवम्बर को प्रधान मंत्री के संकल्प द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को दुहराता है । भारत एकमत हो कर प्रधान मंत्री और उन की नीतियों का समर्थन करता है, जो कि उन्होंने चीनी खतरे को दूर करने के लिए निर्धारित की है ।

कोलम्बो में आज तटस्थ देशों का सम्मेलन शुरू हो रहा है । वे देश हमारे मित्र हैं और हम उन की बैठक का स्वागत करते हैं । हम उन सब देशों की सराहना करते हैं जो युद्ध को बन्द कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

नवीनतम चीनी वक्तव्यों से उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों से प्रकट होता है कि चीन को अपनी शक्ति पर गर्व है । भारत लड़ना नहीं चाहता था । उस ने हमें लड़ने पर मजबूर कर दिया था और अब वह समझौते के लिए हमें अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, जो कि हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते ।

हमारे प्रधान मंत्री ने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उस भावना से दिये हैं जो यह सदन दुहरा चुका है । हमने कह दिया है कि समझौते की बातचीत के लिए कम से कम कार्यवाही की जा सकती है वे यह है कि चीनी पहले ८ सितम्बर, १९६२ से पहले वाली स्थिति बहाल करें । प्रधान मंत्री ने फिर इस मांग को दोहराया है ।

प्रधान मंत्री ने यह भी ठीक कहा है कि नैतिक दृष्टि से चीन अब बिल्कुल अलग हो चुका है ।

संसार के ६० देशों ने हमारे समर्थन की खुली घोषणा कर दी है । साम्यवादी देशों में भी अल्बानिया को छोड़ और किसी ने भी चीन का समर्थन नहीं किया । आज हमारे ही प्रधान मंत्री राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक हैं, मेरा कहना है कि चीन को उनकी यह बात मान लेनी चाहिए कि ८ सितम्बर, १९६२ की स्थिति कायम कर दी जाय । मेरे विचार में प्रधान मंत्री इस बात पर राजी हो जायेंगे कि मामला अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

जाय । इस संदर्भ में हम अपने मित्र देशों के कोलम्बो में हो रहे सम्मेलन का स्वागत करते हैं। इस बात की भी आशा करते हैं कि वे शत्रुता को दूर करने और हमारे देश के लिए किसी सम्मान तथा गौरव के उपयुक्त आधार तलाश कर सकें ।

हमारे प्रधान मंत्री ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसका आधार कुछ सिद्धान्त है, परन्तु चीन अपनी ताकत पर अड़ा हुआ है । जिस तरह उसने शांतिप्रिय भारत को युद्ध करने पर बाध्य कर दिया है, उसी तरह अब वह अपनी शर्तें भारत के ऊपर लादना चाहता है । हम संसार को बताना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं और हमने अपनी शर्तें स्पष्ट बता दी हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नैतिक बल का प्रभाव भी कम नहीं होता । भौतिक शक्तियों द्वारा उस प्रकार का प्रभाव पैदा नहीं किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का जहां तक सम्बन्ध है चीनियों के अहंकार ने साम्यवाद के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को मिटा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी । हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में यदि साम्यवाद ने पनपना है तो उसे कहीं बाहर से नहीं लादा जा सकता । मुझे तो चीन की इस नीति पर बहुत ही खेद है । अमरीका की विदेश नीति में भी कुछ लचीलापन है, परन्तु चीन अपनी ही दुनिया में रम रहा है । उसने इस प्रकार के कदम उठा कर बहुत ही भयंकर कार्य किया है और इसके बहुत ही बुरे परिणाम होने वाले हैं ।

हमारे प्रधान मंत्री देश में एकता क़ायम करने में लगे हुए हैं। मैं उनसे सैद्धान्ततः पूर्ण रूप से सहमत हूं । मैं उनकी इस बात में भी तारीफ करता हूं कि वह शीघ्रता से कोई कदम उठाने के पक्ष में नहीं हैं। जल्दबाजी में कदम उठाने से विश्व शांति को भारी खतरा हो सकता है । हमारी सफलता का आधार नैतिक बल एवं भौतिक तैयारी के संयोग पर निर्भर है । एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के सिद्धान्तों को कुचल देने के कारण चीन संसार भर में अकेला रह गया है । चीन कुछ भी शरारत करता रहे परन्तु मेरा निवेदन यह है कि हमें राष्ट्रीय एकता को कायम रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए और आज के संकल्प की भावना को इसी दृष्टि से देखना चाहिए ।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रतिरक्षा मंत्रालय में परिवर्तन करने पर मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं ।

२० अक्तूबर, १९६२ की तारीख हमारे इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात करती है । उस दिन हमने अपनी उदासीनता को छोड़ कर वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया । परन्तु सरकार के ८ सितम्बर की लाइन सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उस शपथ के विरुद्ध होगा जो हमने सभा में ली थी यह बात जनता की आशाओं तथा आकांक्षाओं के भी विरुद्ध होगी । हमें आक्रामक को अपनी एक एक इंच पवित्र भूमि से निकाल देना चाहिये । ८ सितम्बर की लाइन मान लेने से चीनियों के पास हमारी १४,००० वर्गमील भूमि बनी रहेगी ।

चीन की ओर से शान्ति का प्रस्ताव आने के दो कारण हो सकते हैं । उन्होंने आगे बढ़ने में इतनी तेजी से काम लिया कि उनके लिये सम्भरण कायम रखना कठिन हो गया । दूसरे यह आक्रमण करिबि-

†मूल अंग्रेजी में

यन की घटना के समय यह सोच कर किया गया होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका उधर उलझा हुआ होगा। परन्तु घटनाक्रम के नये मोड़ से उनको निराश होना पड़ा। हमारी प्रारम्भिक हारों ने भी हमको अधिक दृढ़ निश्चित एवं संगठित बना दिया।

चीन के कदम के पीछे छिपे हुये इरादे जानने के लिये हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। माओत्सेतुंग के लेख उसका संकेत करने के लिये पर्याप्त हैं। चीन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से हम अपने बहुत से राज्य क्षेत्र से वंचित हो जायेंगे और हम वहां अपनी चौकियां नहीं स्थापित कर सकेंगे। इससे चीन को सामरिक दृष्टि से उपयोगी क्षेत्र मिल जायेगा और हमारे पड़ौसियों पर बुरा असर पड़ेगा। उनका प्रस्ताव हमें अपमानित करने का षडयन्त्र है तथा उसे सर्वथा ठुकरा दिया जाना चाहिये। बातचीत पर जोर देने से कोई लाभ नहीं होगा।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थिति को देखते हुए, हमें पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने चाहियें और हमें अपनी तटस्थता की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये ताकि हमें बिना भुगतान किये शस्त्रास्त्र सहायता मिल सके। हम युद्ध को जीतने के लिये शान्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा तो यह भी मत है कि हमें यह प्रश्न राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिये। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में दल के बाहर से भी योग्य व्यक्तियों को लेकर उसका आधार व्यापक बनाना चाहिये। आज हमें इस संकट काल में सरदार पटेल की याद आ रही है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के प्रश्न को दलीय दृष्टिकोण से नहीं प्रत्युत् राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इन शब्दों से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री ढेबर** (राजकोट) : प्रधान मन्त्री के संकल्प पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया है, इसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं। मेरा निवेदन है कि चीन सरकार नवीनतम वक्तव्य भारत के लिये चुनौती है। हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व को यह बतायें कि चीन के युद्ध विराम प्रस्तावों का क्या अभिप्राय है। सर्वप्रथम, उनकी एक पक्षीय युद्ध विराम घोषणा से यह प्रतीत होता था कि जैसे उन्हें भारत की ओर से किसी प्रकार की आशा नहीं है। इन तीन प्रश्नों का का भारत सरकार की ओर से उत्तर देने का प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ? स्पष्टतः सम्पूर्ण विचार प्रौपेगेण्डा मात्र है।

चीन पूर्ण रूप से सशस्त्र है और इतनी विशाल सेना का काम केवल अपने देश की सीमा रक्षा करना ही नहीं है। वे चाहते हैं कि भय की अभिव्यंजना,धमकी अथवा आन्तरिक तोड़ फोड़ का आश्रय लेकर एशिया में एक के पश्चात् दूसरे देश को खण्डित करना है। किन्तु भारत की पैंतालीस करोड़ जनता ने विकास की योजना को अंगीकृत किया है। यह एक ऐसी योजना है जिसने अविकसित देशों के समक्ष मानवीय स्वतन्त्रता का विकल्प आधार प्रस्तुत किया है।

चीन के इरादे स्पष्ट जाहिर हैं। हमारा देश भी दृढ़ संकल्प है। आज देश में जनता में स्वाभाविक रूप से प्रसूत व्यापक चेतना को सही दिशा देने की आवश्यकता है। हमारे यहां वृहद् संख्या में श्रमिक शक्ति के अजस्त्र स्रोत हैं। यदि हम इनका समुचित उपयोग करें तो इससे हमें संसाधन प्राप्त होकर शत्रु का सामना कराने का सामर्थ्य मिलेगा। मैं सदन से अपील करता हूं कि देश रक्षा के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हुए हमें सरकार को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सैनिक संघर्ष में हमें अपने समस्त भौतिक साधन सरकार के सुपुर्द कर देने चाहियें।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : हमारे नेता ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह देशभक्ति से परिपूर्ण है और देश के लाखों लोगों की आवाज है। मैं इसका समर्थन करता हूं। राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दासप्पा]

अवसर बहुत ही कम आते हैं जबकि हमें अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान कर देना होता है। आज ४३ करोड़ व्यक्ति देश के प्रत्येक संकट का मुकाबला करने के लिये निश्चित धारणा से खड़े हैं। देश के सभी वर्ग प्रधान मन्त्री को अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो कुछ प्रधान मन्त्री ने किया उसी से हम अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते थे और संसार की आंखों में ऊपर उठ सकते थे। दृढ़ निश्चय से आज हमने अपने कर्तव्य को करने का निश्चय किया है। चीज ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव उसी पुराने सिद्धान्त का परिपोषण करते हैं। उनका सिद्धान्त यह है कि पहिले आक्रमण किया जाये बाद में शान्ति के नाम पर अथवा किसी अन्य बहाने से समय प्राप्त करने का अवसर लिया जाय। सारे चीन के इतिहास में जो भी उथल पुथल हुए हैं उसके अन्तर्गत यह सिद्धान्त काम करता हुआ दिखाई देता है।

इसके अतिरिक्त मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि चीनी लोग झूठा प्रचार करने में बहुत ही दक्ष हैं। अतः हमें अब भी इस बात से सतर्क हो जाना चाहिए कि प्रचार सम्बन्धी उनके साधन हमारी कल्पना से कहीं अधिक सशक्त हैं। इन बातों को देखते हुए हमारी सरकार को अपने प्रचार साधनों को सबल बनाना चाहिए। दुनिया के ६० राष्ट्रों ने भारत का समर्थन किया है। साम्यवादी देशों में केवल एक देश ने चीन का पक्ष लिया है। भारत के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए साम्यवादी देशों ने भी तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। इन सब को देखते हुए भी खेद का विषय है कि चीन अपने इरादों पर अभी भी अड़ा हुआ है। हमें अपने प्रचार साधनों का प्रयोग एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों को अपना दृष्टिकोण समझाना चाहिए।

श्री प्र० के० देव ने तटस्थता की नीति पर पुनर्विचार करने की बात कही है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि आज की स्थिति में हमें तटस्थता की नीति के बारे में परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। हमारी इस नीति की सराहना वे देश भी कर रहे हैं जो हमें सहायता दे रहे हैं। वे हम से यह यह आशा भी नहीं रखते कि अपनी इस नीति का त्याग कर दें। आज तो रूस और चीन के सम्बन्धों में भी खिंचाव है। रूस तो सचमुच शान्ति चाहता है। परन्तु चीन ने हमें काफी हानि पहुंचाई है। खैर हमने संकट का मुकाबला करना है। इसके लिए सरकार को अपना सम्भव सहयोग देना है ताकि अन्ततोगत्वा विजय देवी हमको ही अपना आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** (मंदसौर): हम आज युद्ध विराम की चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में मेरा विचार है कि वर्तमान परिस्थिति में युद्ध विराम का स्वीकार कर लेना पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देने के बराबर है। जो कुछ हो रहा है यह तो चीन वालों की एक पूर्व निश्चित चाल है। माओत्से तुंग का सिद्धान्त इस बारे में प्रसिद्ध है कि अग्रेतर अतिक्रमण के लिए समय प्राप्त करके शत्रु को मारा जाय। चीन के प्रति हमने जो नीति अपनायी रखी उसके बारे में मेरा मत यह है कि हम भारी भूल करते रहे हैं। इस दिशा में हमने भारी भूलें की हैं। हम उन पर विश्वास करके ही आज की परिस्थिति को पहुंचे हैं। स्पष्टतः धोखा खाने वाली बात है।

हमारा जो चीनियों से संघर्ष हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और खेदजनक बात यह है कि हमारे २०,००० सैनिक चीन के ३ लाख सैनिकों का मुकाबला करते रहे हैं। और भी तनिक गहराई

---

†मूल अंग्रेजी में

से देखा जाय तो पता चलेगा कि लड़ाई तो केवल ४००० ने ही की, १६,००० को तो अलग कर दिया गया था। इस समय की ही बात कहनी चाहिए कि चालाक तथा धोखेबाज की वीर तथा बुद्धिमान पर पर विजय हुई है।

मामले को न्यायालय में ले जाने की चर्चा भी हुई है, इस बारे में मेरा निवेदन है कि प्रधान मन्त्री को हेग न्यायालय में मामले को ले जाने का अच्छा परामर्श नहीं दिया गया है। वैसा तब ही किया जा सकता है यदि १४ नवम्बर को सभा द्वारा पारित संकल्प को पूरा कर दिया जाय। परन्तु इस प्रकार की अभी कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती।

पाकिस्तान से वार्ता की चर्चा चल रही है। इस बारे में मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान के साथ समझौता वार्ता में हमें बहुत सावधान रहना चाहिये। यदि पाकिस्तान और चीन में कोई गुप्त करार हो चुका है, तो हमारे प्रधान मंत्री द्वारा उसे बताया जाना चाहिये था। इस के साथ ही उस तथ्य को उन देशों के नोटिस में भी लाया जाना चाहिये था जोकि हमारी सहायता कर रहे हैं। मेरे विचार में पाकिस्तान ने काश्मीर के बारे में काफी भ्रांति फैला रखी है। हमें सभी साधनों द्वारा इस गलत भ्रांति का निवारण करना चाहिये। इस के लिये संसद् के ५० सदस्यों का एक शिष्टमंडल विदेशों में भेजा जाना चाहिये। ऐसा करने से पाकिस्तान द्वारा फैलाई गलतफहमी को अच्छी प्रकार से दूर किया जा सकेगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : आज जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस में यह शब्द लिखे हैं कि हम सीमा स्थिति पर आज विचार कर रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि हम सीमा स्थिति के बजाये युद्ध स्थिति पर इस समय विचार कर रहे हैं। इसी आधार पर मैं समझता हूं कि चीनियों ने २० अक्तूबर को जो हमला किया वह हमारे खिलाफ युद्ध ही है और उस से केवल संसार को ही नहीं अपितु हमारे आलस्य को भी जगा दिया है। हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बात को माना है कि चीनियों को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्हों ने हमारे देश में एकता ला दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीनियों ने हमारे ऊपर तैयारी कर के विश्वासघात के द्वारा हमला किया और इसलिये उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और हम उन को निकाल कर ही दम लेंगे। उन के इन वाक्यों से यदि किसी के मन में कोई संदेह था वह भी दूर हो गया है तथा अब समस्त जनता इस अतिक्रमण से भारत को स्वतंत्र कराने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसलिये अब सरकार को भी अपने सभी साधन जुटाने चाहियें जिस से इस कार्य को पूरा किया जा सके।

कई वर्षों तक हम चीन से शांतिपूर्ण बातचीत की निरर्थक चेष्टा करते रहे। यदि हम २४ अक्तूबर तथा २१ नवम्बर के उन के प्रस्तावों को देखें तो हमें उन के ७ नवम्बर, १९५९ को भेजे गये प्रस्तावों में कोई अन्तर मालूम नहीं होता है। उस समय भी चीन के प्रधान मंत्री ने यही कहा था कि दोनों की सशस्त्र सेनायें 'मैकमहोन' लाइन से उत्तर पूर्व में तथा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण की रेखा से २० किलोमीटर पीछे हट जायें। इसलिये मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण के लिये अब हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये और उन के प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार कर देना चाहिये तथा समस्त मित्र देशों से सहायता ले कर अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। हमारे देश का पूर्ण ध्यान एकता तथा सैनिक शक्ति को दृढ़ करने पर केन्द्रित होना चाहिये ताकि उचित समय में हम अपने खोये हुए क्षेत्र को वापस ले सकें।

मैं इस बात पर बल देता हूं कि अब हमें राजनयिक माध्यम द्वारा समस्या को हल करने पर ध्यान नहीं देना चाहिये क्योंकि अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तो हमें अपना हारा हुआ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

प्रदेश वापस लेना है क्योंकि हम ने इस की प्रतिज्ञा कर ली है । मेरा यह कहने से यह मतलब नहीं है कि इस को कल को ही वापस ले लेना चाहिये । यह काम हमें हमारी सेनाओं को उचित समय देख कर करना है । मैं तो केवल यही चाहता हूं कि ऐसा करने का दृढ़ निश्चय जो हम ने कर लिया है कहीं हमारी सरकार उस से न डिग जाये । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हिटलर ने आस्ट्रिया और चैकोस्लोवाकिया को जीत लिया था तो ब्रिटेन के पास शांति का प्रस्ताव भेजा था परन्तु ब्रिटेन ने उसे अस्वीकार कर दिया था । हमें भी ऐसा ही बर्ताव करना चाहिये और अपनी शक्ति बढ़ा कर हारे हुए प्रदेश को वापस लेने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मुझे प्रधान मंत्री का यह कहना अच्छा नहीं लगा कि यदि चीनी ८ सितम्बर, १९६२ की लाइन से पीछे हट जायें तो हम बातचीत करने को तैयार हैं क्योंकि इस सुझाव को तो चीनियों ने अस्वीकार कर दिया है । मुझे उन का यह सुझाव भी ठीक नहीं लगा कि वह मामले को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत को सौंपने को तैयार हैं । क्योंकि चीन सरकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणों तथा आचरणों को मानती ही नहीं है । इस के अतिरिक्त यदि इस युद्ध विराम स्थिति में हम ने मामला अन्तर्राष्ट्रीय अदालत को सौंपा तो चीनी उस स्थान से नहीं हटेंगे जिस पर उन्हों ने कब्ज़ा कर रखा है और मैं समझता हूं कि यह युद्ध विराम रेखा भी उसी प्रकार से स्थायी बनी रहेगी जैसीकि काश्मीर की युद्ध विराम रेखा बनी हुई है । मुझे भय है कि अन्तर्राष्ट्रीय अदालत अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ में इस सवाल को ले जाने पर इस का भी वही हाल होगा जो आज काश्मीर का है और जिस भूमि पर चीनियों ने अधिकार कर लिया है उस पर काश्मीर के समान ही उन का अधिकार स्थायी न हो जाये ।

मैं भारत तथा पाकिस्तान के बीच वार्ता का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि हमारे मतभेदों को दूर होना चाहिये तथा हमारे पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे तथा मित्रतापूर्ण होने चाहियें ।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने बताया कि चीनी चाहते हैं कि हम अपनी तटस्थ नीति छोड़ दें, परन्तु हम उस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे । हमें अभी भी विदेशों से सहायता मिल रही है चाहे वह रूस हो अथवा अमरीका । इसलिए हमें इस अपनी नीति को छोड़ने के सम्बन्ध में सोचना भी नहीं चाहिये ।

हमें प्रसन्नता है कि लंका में अफ्रेशियाई देशों का सम्मेलन चीन-भारत विवाद के हल पर विचार करने के लिये हो रहा है । परन्तु मैं यह नहीं समझा कि सरकार ने लंका में एक ग़ैर-सरकारी शिष्टमंडल को वहां पर जाने की इजाज़त क्यों दे दी है । ऐसे व्यक्तियों को वहां जाने की इजाज़त कभी भी नहीं दी जानी चाहिये ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : मेरे मित्र जनसंघ के नेता श्री त्रिवेदी ने कहा कि युद्ध विराम हथियार डाल देने के समान हुआ है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि चीन ने यह युद्ध विराम अपनी तरफ से किया है । हम ने तो केवल अपनी तरफ से गोली चलाना बन्द कर दिया है और हम उन के द्वारा की गई इस घोषणा के आधार पर ही बातचीत करने को कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं । बातचीत करने के बारे में प्रधान मंत्री सवेरे बता चुके हैं कि जब तक चीनी ८ सितम्बर की लाइन तक हट नहीं जाते हैं तब तक बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री ने मामले को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत को सौंपने के बारे में भी यही शर्त रखी है कि चीन को पहले ८ सितम्बर, १९६२ की लाइन तक हट जाना चाहिये। हमने १४ नवम्बर को सभा में खड़े हो कर भी इस पृष्ठभूमि के आधार पर शपथ ली थी कि बातचीत अथवा समझौते का कोई काम तभी हो सकता है जब चीन ८ सितम्बर की लाइन तक हट जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : संकल्प में यह नहीं था।

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह संकल्प में तो नहीं था परन्तु संकल्प को इसी पृष्ठभूमि के आधार पर पारित किया गया था।

परन्तु अब इस बात का प्रमाण मिल चुका है कि चीन सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने कोलम्बो में हो रहे छः राष्ट्रों के सम्मेलन से कुछ समय पहले यह घोषणा कर दी कि वह भारत के २७ अक्तूबर के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। इस से स्पष्ट हो जाता है तथा सिद्ध हो जाता है कि चीनी, पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में अपने अतिक्रमणों से प्राप्त लाभों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे सैनिक निर्णय चाहते हैं तथा समझौता वार्ता नहीं। उनका रवैया तानाशाही है। उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री से जो तीन सवाल पूछे हैं वह एक प्रकार का अल्टीमेटम है, चुनौती है। उन की शांति स्थापना की कोई इच्छा नहीं है और वह लद्दाख में अपने कब्जे में आये किसी भी स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है।

मैं २९ नवम्बर के चीनी वक्तव्य के बारे में यह कहना चाहता हूं कि चीनियों ने इस में भी २४ अक्तूबर के अपने प्रस्तावों को ही मनवाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने उस में कहा है कि यदि हम पश्चिम अथवा मध्य क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण की रेखा के दक्षिण में २० किलोमीटर नहीं हट जाते हैं अथवा पूर्वी क्षेत्र में मैकमाहोन रेखा के निकट आते हैं तो वह पुनः लड़ाई शुरू कर देंगे। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि यदि पूर्वी क्षेत्र में हम ने ढोला अथवा लौंगजू को पुनः लेने का प्रयत्न किया अथवा चिपचैप नदी घाटी अथवा गलवान घाटी में चौकी बनाने का प्रयत्न किया तो भी लड़ाई शुरू कर दी जायेगी। यह तानाशाही नहीं है तो और क्या है।

१९५६ में चीन सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि उन का भारत की भूमि पर कोई दावा नहीं है तथा उन नकशों में भारत का जो भाग चीन का अंग दिखाया गया है वह पुराने नकशे हैं और उन को ठीक किया जायेगा। परन्तु १९५७ में उन्होंने हमारा प्रदेश अपने कब्जे में कर लिया तथा सिंकियांग तिब्बत सड़क बना ली।

सबसे पहले जनवरी, १९५९ में चीनियों ने स्पष्टतया बताया कि भारत की ५०,००० वर्गमील भूमि उन की है। इस के बाद जब चीन और भारतीय अधिकारियों की दिल्ली, पैकिंग और रंगून में बातचीत हुई उस समय चीनियों ने भारत के अधिकारियों को बताया कि नेफा की चार डिवीजन उन की है तथा लद्दाख में रूढ़िगत सीमा रेखा तक उन की भूमि है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र में जो उन्होंने हमारा इलाका ११,००० से १२,००० वर्ग मील हड़प लिया है उन का विचार उस को छोड़ने का नहीं है। इस के अतिरिक्त वह यह चाहते हैं कि हम अपने इलाके से २० किलोमीटर हट जायें अथवा दौलतबेग ओल्दी, मुर्गो अथवा चुशूल को भी छोड़ दें। मैं समझता हूं कि उन की इन शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि ये शर्तें बड़ी अपमानजनक हैं। हमारे साथ विश्व के बहुत से राष्ट्र हैं तथा चीन का समर्थन केवल एक देश अल्बानिया ने किया है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री ने उन के ऐसे अपमानजनक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : अब यह नितांत स्पष्ट हो गया है कि चीन के सैद्धान्तिक तथा भारत के प्रति विस्तारवादी उद्देश्य हैं। इस कारण हमने पक्का निश्चय कर लिया है कि हम राष्ट्र रूप में उनका सामना करेंगे तथा अन्त तक लड़ते रहेंगे।

इसके साथ साथ हमें रूस, अमरीका तथा ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्धों का भी ध्यान रखना चाहिये। हमें याद रखना चाहिये कि रूस ने हमारी कई बार कठिन परिस्थितियों में सहायता की है। परन्तु साथ ही साथ हमें अमरीका तथा ब्रिटेन का भी आभारी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने आज हमारी सहायता के लिए हाथ पसारा है। हमें अब प्रयत्न करना चाहिये जिनसे अफ्रेशियाई देश हमारी बात का समर्थन करें।

सब जानते हैं तथा हमारे प्रधान मंत्री भी स्पष्ट कह चुके हैं कि मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र में मैकमाहोन लाइन हमारी निश्चित सीमा रेखा है परन्तु पश्चिमी क्षेत्र अर्थात् लद्दाख के बारे में कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है। इस क्षेत्र में सीमा केवल परम्परागत है जिसमें कोई बनस्पति नहीं उगती है। इस क्षेत्र की हमारी सीमा का अंकन नहीं किया गया तथा बताया भी नहीं गया कि यह किन किन स्थानों से गुजरती है। अंग्रेजी शासनकाल में काश्मीर के महाराजा से एक संधि अंग्रेजों ने की थी तथा महाराजा ने ही कई संधि तिब्बत से इस सम्बन्ध में की थीं। उनमें से एक संधि पर तत्कालीन चीन के शासक के भी हस्ताक्षर हैं। उन्हीं संधियों से तिब्बत और चीन के बीच परम्परागत सीमा का आभास मिलता है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि हमारा मतभेद केवश पश्चिमी सीमा अर्थात् लद्दाख के बारे में हो सकता है तथा पूर्वी तथा मध्य भाग के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता और बातचीत भी दूसरी सीमा के बारे में की जा सकती है तथा समझौता किया जा सकता है जो हमारे लिये सम्मानीय हो।

हम इस बात को सपष्ट कर चुके हैं कि हम चीन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें चीन ने बता दिया है कि हमें उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। इसलिये अब हमें सावधान रहना चाहिये और सीमा को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जिससे दोबारा कोई आक्रमण करे।

मेरे मित्र श्री त्रिवेदी ने काश्मीर का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि काश्मीर भारत का अंग बन चुका है और इस बात को सबने स्वीकार कर लिया है। जब अंग्रेज़ों ने हमें स्वतन्त्र किया उस समय काश्मीर के शासक ने काश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए ही कहा था। इस प्रकार काश्मीर का भारत में मिलना पूर्णत: विधिक तथा संवैधानिक है। परन्तु खेद है कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला कर दिया और हमें युद्ध विराम रेखा को मानना पड़ा। मैं युद्ध विराम के समय की एक घटना को आप के सामने रखना चाहता हूं। युद्ध विराम रेखा जिस इलाके में से गुजरती थी उसमें दो गांव बीच में पड़ते थे जिनकी जनसंख्या २००० से भी अधिक थी। उनसे जब पूछा गया कि वह भारत में आना चाहते हैं अथवा पाकिस्तान में तो मैं बताना चाहता हूं कि वह शतप्रतिशत मुसलमान होते हुये भी भारत में ही आये। परन्तु अब तब से बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं और जिहाद के नाम पर लोगों के मनों में अन्धविश्वास और कट्टरता की भावनायें भरी जा चुकी हैं।

स्पष्टतया सब जानते हैं कि हमने सर्वथा दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का विरोध किया है तथा कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वाधीनता प्राप्त की। इसलिए

†मूल अंग्रेजी में

हमें अब एक राष्ट्र के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करना चाहिये तथा आक्रमणकारी को देश से निकालने का मिल कर पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : जब से चीनियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तब से संसद् तथा देश में इस प्रकार की भावनायें फैल रही हैं कि अब क्या होगा । परन्तु मुझे आज प्रधान मंत्री का भाषण सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय से आज कह दिया कि जब तक भारत का एक-एक इंच राज्य क्षेत्र वापस नहीं ले लिया जायेगा तब तक हम युद्ध की तैयारी जारी रखेंगे ।

एक महीने में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं कि जिनके कारण देश में लोगों के सामने बहुत से प्रश्न आ गये हैं । क्या हमारा सैनिक गुप्तचार विभाग अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाया । क्योंकि नेफा क्षेत्र की जितनी जानकारी चीनियों को रही उतनी भारतवासियों को नहीं रही । ऐसा मैं इस कारण से कह सकता हूं क्योंकि चीनियों का हमला इस प्रकार का हुआ कि हमारे सैनिक हक्के बक्के रह गए । मैं चाहता हूं कि इन सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए ।

चीनियों ने जिस प्रकार युद्ध विराम की इकतरफा घोषणा की है उससे मालूम होता है कि उन्होंने हम सबको परीक्षा के लिए खड़ा कर दिया है । हम गोली चलायें अथवा नहीं । परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी तरफ से भी युद्ध विराम हो गया है । प्रधान मंत्री के वक्तव्य ने स्थिति स्पष्ट कर दी है परन्तु इसके सांथ साथ सरकार को हमें यह भी बताना चाहिये कि उसका क्या करने का विचार है । चीन हमको "अल्टीमेटम" दे रहा है कि या तो २० कलोमीटर पीछे हट जाओ वरना हम पुनः लड़ाई जारी कर देंगे । इसलिए आवश्यक हो जाता है कि प्रधान मंत्री हमको बतायें कि उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे चीनी हमारे इलाके से निकाल दिए जायें अथवा निकल जायें । क्या हमारा विचार चीनियों के जाने के बाद मैकमाहोन लाइन तक पहुंच जाने का है । क्या वहां पर असैनिक प्रशासन स्थापित करने का है ? इन प्रश्नों का पूरा पूरा उत्तर दिया जाना चाहिये ।

समस्त देश ने इस बात का समर्थन किया है कि चीन को ८ सितम्बर की स्थिति में आ जाना चाहिये । यदि सभा में इसके बारे में स्पष्टतया बता दिया जाये कि हम तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक चीन ८ सितम्बर की स्थिति में नहीं आ जाता है तथा उनके द्वारा छोड़े गये इलाके में हम किस प्रकार का प्रशासन करना चाहते हैं, तो हमारे सभी संदेह दूर हो जायें ।

कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि सरकार का पुनर्गठन किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री उन के इन सुझाओं पर जरूर विचार करेंगे । परन्तु मैं यह ठीक नहीं समझता कि वर्तमान संकट की घड़ी में सरकार में कोई परिवर्तन किया जाये । वर्तमान सरकार ने पूरी योग्यता से काम किया है तथा इस सभा और समस्त देश ने इस सरकार की नीति का समर्थन किया है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस सरकार को बदलना अथवा बदलने की मांग करना व्यर्थ की बात है ।

तटस्थता की हमारी नीति की लगभग समस्त विश्व ने प्रशंसा की है इसलिये इस नीति में परिवर्तन करने की मांग करना भी शोभनीय नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री याज्ञिक]

हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना है। तथा सैनिकों की संख्या बढ़ानी हैं। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि हमें आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों को अपनी सेना में बुलाना चाहिए तथा उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा यह भी सुझाव है कि केवल सेना ही हमारी जीत के लिए पर्याप्त नहीं है अपितु प्रशासन में ऊपर से लेकर नीचे तक समस्त श्रेणियों में गतिशील शक्ति की भावना उत्पन्न की जानी चाहिये। मेरा प्रधान मंत्री समेत सभी मंत्रियों से अनुरोध है कि अपने समस्त प्रशासन में परिवर्त्तन करके उसे अधिक दक्ष बना दें।

अन्त में मैं जनता के सहयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पहला मौका है जब देश में इतना जागरण हुआ है। हमें इस जागरण को देख कर गांधी जी की याद आ जाती है। सरकार को प्रयत्न करना चाहिए ऐसे समय में पूंजीपत्तियों से मजदूरों को बचा के तथा उत्पादन में मज़दूरों का शोषण हुए बिना वृद्धि हो।

†**श्री खाडिकलकर** (खेड) : चीनियों के अकारण आक्रमण से देश में बहुत जाग्रति पैदा हुई है और इससे हमें उन बुनियादी बातों पर फिर से सोचने का मौका मिला है जो इस युद्ध में अन्तर्ग्रस्त है। यद्यपि सीमा पर एक युद्ध में हमारी फौज की हार हुई है इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस युद्ध में भारत की हार हुई है।

चीन के लिये एकपक्षीय युद्ध विराम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा। वे भारत से शक्ति के जोर पर वार्त्ता करना चाहते हैं।

वस्तुतः सच्चाई यह है कि चीन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्यवादी क्रांति का प्रसार कर रहा है। यह प्रसार हिंसा के द्वारा किया जाना है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

युद्ध और शांति के आधारभूत सिद्धान्त न केवल भारत के लिये अपितु समस्त विश्व के लिये उनमें अन्तर्ग्रस्त हैं। चीन की युद्ध विराम घोषणा एक चाल है यह हमें बदनाम करने का साधन है।

हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम चीन की इस चाल के सामने कभी पराजित नहीं होंगे। इस समय चीन अकेला पड़ गया है और पीछे हटने को तैयार है। उसने अंधाधुंध प्रचार करना शुरू कर दिया है।

हमें अपने नेतृत्व को कमजोर नहीं बनाना चाहिये। युद्ध में नेतृत्व का बहुत महत्व होता है, हमारे मामले में यह केवल युद्ध के नेतृव का प्रश्न नहीं है वरन् आदर्शों के नेतृत्व का भी प्रश्न है: केवल लड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि जिम बात के लिये हम लड़ रहे हैं वह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। सब लोगों को यह समझना चाहिये कि हम समाजवाद के लिये लड़ रहे हैं।

अतः मैं यह चाहता हूं कि सभा को कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों को यह बताना चाहिये कि हम पर चीन के झूठे प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होगा तथा हम शक्ति के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कालिदास के एक श्लोक से शुरू करूंगा।

अस्तुवरं इन्दा दिशि देवलात्मा

हिमालयो नाम नगाधिराजः,

पूर्वा परोवारिनिधी विगाह्यय, स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः ।

हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर हिमालयराज पूर्व के समन्दर का अवगाहन करता हुआ हमारे मानदंड की भांति स्थित है। आज वही हिमालय चीनी आक्रमण से अपमान से पीड़ित और घायल पुकार रहा है और कह रहा है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ।

हर्ष की बात है कि देश ने उसकी पुकार सुन ली। पर साथ ही दुःख भी है कि अभी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। हिमालय की रक्षा के बगैर देश की रक्षा सम्भव नहीं है।

हें हें उत्तर कीजिये"। अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको चेतावनी दी थी कि वे सोचें। जब मैं हिमालय की बात करता हूं, हिमालय की रक्षा की बात करता हूं तो इसलिये करता हूं कि हिमालय की रक्षा के साथ साथ इस देश की रक्षा जुड़ी हुई है। अगर हिमालय सुरक्षित नहीं है तो शायद हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे। देश की रक्षा तिब्बत, भूटान, सिक्किम आदि के साथ जुड़ी हुई है। मैंने जो कहा कि मुझे दुःख है वह इसलिए कहा कि माननीय प्रधाग मंत्री जी, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और जो इस समय बैठे हुए हैं, जब भी तिब्बत का प्रश्न आता है तो कह देते हैं कि तिब्बत की बात करना "मैनीफैस्ट नानसेंस" है। वह कहते हैं कि हजारों वर्षों से तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है। जब ऐसी बात होती है, तो बहुत दुःख होता है। और पता चलता है कि सरकार शायद हिमालय की रक्षा नहीं करने जा रही है—अगर वह करे, तो अच्छा है—इसीलिये मैं इस को दोहरा रहा हूं। इस बात में कितना दम है, यह इस से प्रकट है कि इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्रप्रसाद, ने तो कहा है कि हम ने तिब्बत की आज़ादी को खोया, हमें उस का प्रायश्चित करना है और वह प्रायश्चित तभी हो सकता है कि हम अपनी रक्षा करें, हिमालय की रक्षा करें और तिब्बत को आज़ाद करायें। मैं प्रधान मंत्री से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर वह ऐसा नहीं कह सकते कि हम तिब्बत को आज़ाद करायेंगे, तो अगर वह कम से कम अब खामोश रहें, तो ज्यादा अच्छा है।

भारत सरकार आज-कल तिथियों में उलझी हुई है। चीनी आक्रमण आरम्भ हुआ और हमारी काफ़ी भूमि चीन के कब्जे में चली गई, लेकिन हम ७ नवम्बर, १९५९ और ८ सितम्बर, १९६२, इन तिथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर चीन ८ सितम्बर, १९६२ की स्थिति पर चला जाये, तो उस से बातचीत करेंगे। चीन कहता है कि नहीं, ७ नवम्बर, १९५९ की स्थिति के आधार पर बातचीत की जाये। वह इस हद तक कहता है कि ७ नवम्बर, १९५९ की लाइन हिन्दुस्तान के लिए ८ सितम्बर, १९६२ की लाइन से बेहतर है, क्योंकि वह इस से पीछे की रेखा है: समझ में नहीं आता कि जब चीन ७ नवम्बर, १९५९ की लाइन को अपेक्षतया पीछे की लाइन समझता है, तो फिर प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत ८ सितम्बर, १९६२ की लाइन को स्वीकार करने में उसे कौन सी अड़चन पड़ रही है। इस से साफ़ ज़ाहिर है कि उसका युद्ध विराम प्रस्ताव केवल धोखा मात्र है और वह अपनी उस पुरानी नीति पर चल रहा है कि अपने आप को मज़बूत करने के लिये कुछ समय हासिल किया जाये। इस के साथ ही वह दुनिया को यह बताना चाहता है कि चीन तो शान्तिपूर्ण रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन हिन्दुस्तान

[श्री राम सवक यादव]

आक्रमणकारी है और वह चीन पर चढ़ आया है। हिन्दुस्तान को बड़े देशों से मौके पर जो सहायता मिली है और इस देश में जो जागरण उत्पन्न हुआ है, चीन अपने युद्ध-विराम के प्रस्ताव से उन को भी धक्का लगाना चाहता है।

मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस युद्ध-विराम प्रस्ताव को बिल्कुल अस्वीकार किया जाना चाहिये। अब तो ८ सितम्बर, १९६२ वाली लाइन को भी भूल जाना चाहिए और केवल एक ही लाइन को याद रखना चाहिये। और वह कौन सी रेखा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १५ अगस्त, १९४७ को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो भूमि हम को अंग्रेज़ों से मिली, दरअस्ल वही हमारी सीमा-रेखा है, क्योंकि उस लाइन के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, उस में कोई सन्देह नहीं है। अगर हम ७ नवम्बर, १९५९ और ८ सितम्बर, १९६२ की रेखाओं पर चलें, तो कौन फ़ैसला करेगा कि ७ नवम्बर, १९५९ की कौन सी लाइन है और ८ सितम्बर, १९६२ की कौन सी लाइन है। चीनी कहीं भी उन लाइनों को बता सकते हैं। उन लाइनों का कोई हिसाब नहीं है। जंगल, पहाड़, नदी, नाले आदि का प्रश्न उन के सम्बन्ध में उठता है। इन लाइनों में सब गड़बड़, सन्देह, दुविधा और भ्रम है। इस लिए इस भ्रम को दूर करने के लिए भारत सरकार और ख़ास तौर से प्रधान मंत्री को जम कर, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कहना चाहिये कि हिन्दुस्तान की रेखा १५ अगस्त, १९४७ वाली रेखा है, इस के अलावा और कोई रेखा नहीं है। वह निश्चित रेखा है।

श्री त्यागी : पांडीचरी और गोआ वग़ैरह की क्या पोज़ीशन होगी ?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के ज़रिये इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता ने भी उस रेखा को स्वीकार किया है और यह जान कर स्वीकार किया है कि जब हम १५ अगस्त, १९४७ की रेखा की बात करेंगे, तो फिर हम को पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिये कि हमारे बड़े बड़े शहरों में बमबारी हो सकती है, हम विनाश की ओर जा सकते हैं, हमारी आबादी की बहुत बड़ी संख्या मर सकती है और शायद अस्पतालों में घायलों के लिये जगह भी न मिले। यह बात अपने दिमाग़ में रख कर ही जनता ने १५ अगस्त, १९४७ की लाइन की बोली को बोलना शुरू किया है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उन दोनों लाइनों में फर्क क्या है ?

श्री राम सेवक यादव : माननीय सदस्य यह तो प्रधान मंत्री से पूछें। इस लिये सम्पूर्ण युद्ध की घोषणा चाहे न हो, लेकिन सम्पूर्ण युद्ध के स्तर पर हम को तैयार होना है।]

अज भी एक दुविधा की स्थिति है। आज हम लड़ भी रहे हैं और नहीं भी लड़ रहे हैं। हम युद्ध विराम को माने भी नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उस को स्वीकार भी किये हुए हैं और हमारी तरफ़ से कुछ नहीं हो रहा है। यह दुविधा की स्थिति है। चीन के मुकाबले में शुरू में हमारी जो हार हुई, उसकी एक्स्प्लेनेशन और सफ़ाई के रूप में सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हम लड़ाई के लिये तैयार नहीं थे। अगर ऐसी बात है, तो मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब वह कोलम्बो तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो कौन सी तैयारी के आधार पर उन्होंने कह दिया कि हम ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया है कि वह चीन को हमारी सीमा के बाहर खदेड़ दे।

अभी, प्रधान मंत्री ने कहा कि चीन कहता है कि वह अपने को बचा रहा है, अपनी रक्षा कर रहा है और ऐसा कहते कहते वह हमारी ज़मीन पर कब्जा करता चला जा रहा है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन ले रहे हैं। लेकिन अपनी ज़मीन लेने के हमारे इरादे और अपने को बचाने के चीन के इरादे का नतीजा तो मैं यह देखता हूं कि चीन हमारी भूमि पर कब्जा करता चला जा रहा है। उस में हम कोई फ़र्क नहीं पाते हैं।

फिर यह भी कहा जाता है कि चूंकि हम शान्ति का रास्ता अपनाए हुए थे, इसलिये हम ने लड़ाई की कोई तैयारी नहीं की। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने काश्मीर की लड़ाई लड़ी, गोआ की लड़ाई लड़ी और उन में शक्ति का इस्तेमाल किया। इसलिए यह दलील भी ग़लत है।

फिर कहते हैं कि चीन की पल्टनें ज्यादा हैं, उसकी तैयारी ज्यादा है और उसके मुकाबले में हम कमज़ोर पड़ गए। ये सारी बातें ग़लत हैं। हो सकता है कि अंशतः कहीं वे सही हों। सब से सही बात तो यह है कि हम में दुविधा रही और हम ने अभी भी सफ़ाई के साथ यह नहीं कहा कि हम लड़ेंगे। हम बराबर यह बात सोचते रहे कि हम सुलाह करेंगे, समझौता करेंगे। यह बात हमारी सरकार और अधिकारियों के मन में और सीमा पर लड़ने वाले हमारे जवानों के दिमागों में भी रही और इसी लिए हम को चोट और हार खानी पड़ी।

असल में इस बात की सफाई देने में आज सरकार, सरकारी पार्टी, कांग्रेस के बहुत से लोगों और इधर बैठने वाली कम्यूनिस्ट पार्टी, इन तीनों का इरादा एक है। ये तीनों एक साथ मिल गये हैं और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये यह सफाई देते हैं कि चीन की ताकत ज्यादा है, इसलिये हम हारे। अधिकारी भी यही दलील देते हैं मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों से देश का मनोबल गिरता है और जनता में भ्रम तथा घबराहट पैदा होती है।

आज सरकार कहती है कि जो लोग युद्ध की तैयारी में अड़चन डालेंगे, हम उन को जेल भेजेंगे मैं सरकार से निवदन करना चाहता हूं कि उनके कई ऐसे मित्र और दोस्त हैं, उनके अपने दल के ऐसे लोग हैं, जो यह कहते हैं कि चीन की पल्टन चार करोड़ है और उसके पास तीन हजार वायुयान मौजद हैं यह सफाई दी जाती है कि यह नीयत का सवाल है, नीयत से पता लगाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की बातों से जनता का मनोबल नहीं गिरता है, जनता का हौसला नहीं टूटना है, जनता का आत्म-विश्वास नहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा होता है, तो मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं—जिनहोंने बड़ी तेजी से कहा था कि जो लोग लड़ाई की तैयारियां में कमजोरी दिखायेंगे, हम उन को जेल भेज देंगे—कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जा रहा है।

आज प्रधान मंत्री जी कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि वह बहुत ठीक है। मैं भी कहता हूं कि ठीक है लेकिन अगर वह ठीक है, टो उनकी गिरफ्तारियों का मतलब क्या है? अगर उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनके प्रस्ताव और कर्म में फर्क है—प्रस्ताव कुछ है और कर्म कुछ और है। हम तुलसी-कृत रामायण में राक्षसों की कहानियां पढ़ते हैं। राक्षस की क्या परिभाषा है? जो अपने आप को बदलते रहें, कभी जमीन के नीचे चले जायें, कभी जमीन के ऊपर चले जायें, कभी आसमान में चले जायें और कभी हममें और आप में चले जायें और किसी को भी उन का पता न चले यहां पर भी ऐसे लोगों से बहुत सचेत रहने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग टहलते हुये नजर आयेंगे, जिनको हम पहचान न सकें, जिनको हम बहुत अच्छे और भले समझें, लेकिन वे सब उसी तरह के लोग हैं, जो कि सूरत-शक्ल बदल कर हमको धोखा देते आ रहे हैं।

[श्री राम सेवक यादव]

मैं प्रधान मंत्री से कहूंगा कि इस दुविधा की स्थिति को अब समाप्त किया जाये अब दुविधा से काम नहीं चलने वाला है आज जनता का धीरज टट रहा है, इसलिये नहीं कि वह लड़ना नहीं चाहती, इस लिये नहीं कि उसमें साहस या धन की कमी है, बल्कि इस लिये कि उस के सामने कोई साफ बात नहीं रखी जा रही है और उसके सामने एक दुविधा की स्थिति है ।

संकट-कालीन स्थिति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अगर संकट-कालीन स्थिति का मतलब वही ही है, जैसे कि आज काम चल रहा है, तो हम समझते हैं कि संकट-कालीन स्थिति की घोषणा गलत हुई और हमें देखना है कि कहीं अपने विरोधियों को दबाने के लिये संकट-कालीन स्थिति का फायदा न उठाया जाये। हम संकट-कालीन स्थिति की घोषणा करने के लायक सरकार को तब समझते, अगर वह इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये विरोधी पक्ष के लोगों के साथ भी विचार-विमर्श करती। लेकिन आज तक प्रधान मंत्री ने विरोधी पक्ष के किसी भी नेता को, किसी भी सदस्य को, नहीं बुलाया है। हां, यह जरूर हुआ है कि विरोधियों ने कहा है कि जरा हमारी भी सुन लीजिये। क्या मैं समझूं कि यह युद्ध-स्तर की तैयारी है ? क्या इस संकट-कालीन स्थिति का सही रूप में मुकाबला किया जा रहा है ?

इसी तरह से यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनी, उस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन को भी आप देखिये तो वही परिवार की बात, ही आपसदारी की बात उस ओर भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह जब हम कहते हैं कि मितव्ययिता बरती जाय, वार कैबिनेट अर्थात् युद्धकालीन मंत्रिमंडल बनाया जाय तो प्रधान मंत्री कहते हैं कि इतने बड़े मंत्रिमंडल के बिना काम नहीं चल सकता। हमारे राजेन्द्र बाबू ने भी उस ओर इशारा किया, लेकिन उसके लिये भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है आज राज्यों में और केन्द्रीय मंत्रिमंडल इतने बड़े हैं कि उनमें बहुत काट छांट करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको भी कोई सुनने के लिये तैयार नहीं है। जब तक आप महाराणा प्रताप सिंह बनते, तब तक काम नहीं चल सकता है। जब आज हमारे जवान घाटियों में और नेफा में जाकर लड़ सकते हैं तो क्या हमारे मंत्रिगण और हमारी सरकार के अफ़सर अपनी तन्ख्वाहों और भत्तों में, खर्चों में कमी नहीं कर सकते ? उनको थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन वह भी नहीं किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, इसकी मैं आपको मिसाल दूं। अभी हम ने सुना कि बाराबंकी में एक नहर के बड़े अफ़सर के लिये नहर की पट्टी पर पानी का छिड़का हो रहा था यह युद्ध काल है लेकिन विकास खंडों में आज भी उन लोगों की जीपें चल रही हैं। वह जीपें फौज के लिये नहीं ली जा रही हैं। आज जो देशभक्त नहीं, देशद्रोही हैं, जो तेजपुर का पुराना जिलाधीश है, जिसको मुअत्तल किया हुआ है, सुना जाता है उसको कहीं और नौकरी मिल रही है उसको जेल जाना चाहिये क्योंकि वह देश का द्रोही है आज देश भर में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दामों को रोकने के लिये निश्चित दाम नीति नहीं अपनायी जा रही है।

अंत में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। जो हमारा नेफा है, पूर्वीउत्तरी सीमांचल प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल ३५ हजार वर्ग मील है और जहां पर पांच या छः लाख लोग रहते हैं, वहां के रहने वाले कौन हैं ? वे हैं आभोर, आहोर, दफ्ला, मिस्मी, मिकिर आदि आज भी उन लोगों को अपने से अलग रक्खा गया है। आज भी शायद यह नियम है कि कोई और हिदुस्तान का आदमी अगर उस भाग में जाना चाहे तो उसको परमिट की जरूरत होगी। क्योंकि उन लोगों के मामलात में किसी

को दखल देने की जरूरत नहीं है, उनकी सभ्यता वैसो ही बनी रहे, वे आधुनिक न बनें और नई दुनियां के लिये तैयार न हों। आज भी वहां पर जाने के लिये आप ने प्रतिबन्ध लगा रक्खा है। आज वहां चीनी हमले के समय में हमारे डा० राम मनोहर लोहिया गये तो उनको पकड़ा गया लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर हिंदुस्तान का कोई नागरिक उर्वशीयम अर्थात् नेफ़ा जाना चाहे तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

इसी के साथ साथ अन्त में मैं प्रधान मंत्री जी से चाहूंगा कि वे लोक सेना के निर्माण के लिये तत्काल तैयारी करें और साथ ही साथ गुरीला वारफ़ेअर की तैयारी भी की जाय। जहां जहां युद्ध हो वहां की जनता को हम हटायें नहीं, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को छोड़ कर, और वहां की जनता को आखिरी दम तक एक एक इंच जमीन के लिये लड़ाई लड़ने के लिये हथियार दें। तभी जाकर जिस उद्देश्य की घोषणा हुई है उसकी पूर्ति होगी। यदि ऐसा नहीं करते तो मैं कहूंगा कि संकट-कालीन स्थिति की घोषणा करके जो अधिकार लिये गये वे बेमतलब हैं।

यह कहना कि प्रधान मंत्री की नुक्ता चीनी जो है वह देशद्रोह है, यह गलत चीज है आज समय है कि हमारे अन्दर भाव उत्पन्न हों। हम दुखी हैं कि हमारी जमीन चली गई है और सरकार के हाथ से चली गई है आखिर हम कैसे रात दिन इस स्थिति को भूल सकते हैं, और इसीलिये मजबूरन हमको नुक्ता चीनी करनी पड़ती है। नुक्ताचीनी नहीं तो क्या प्रधान मंत्री की आरती उतारी जाये।

इसके बाद मैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही कहना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : आप तो अभी दो बार अपनी अन्तिम बात कह चुके हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : पाकिस्तान का मामला हमारे सामने नहीं है।

श्री राम सेवक यादव: यह बहुत नाजुक बात है इसलिये कहना चाहता हूं पाकिस्तान के बारे में मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम दो दरवाजे खोल कर नहीं चल सकते। चीन का दरवाजा खुला हुआ है और हम चीन से मुकाबला कर रहे हैं इसलिये पाकिस्तान के दरवाजे को जरूर बंद रखना होगा और हमें पाकिस्तान से सुलह समझौता कर के रास्ता निकालना होगा। अच्छा होता कि प्रधान मंत्री अपनी तरफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक संघ बनाने की कोशिश करते। ·

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय): कुछ दिन पूर्व जब चीनियों ने युद्ध विराम घोषणा की थी तो मेरी पहिली प्रतिक्रिया यह हुई कि यह भी चीनियों की एक चाल है। मैंने बी० बी० सी० रेडियो से अपने एक भाषण में बताया कि सरकार भले ही इन शर्तों को स्वीकार कर लेवे तथापि जनता इन अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं होगी।

इस समय मेरा मत यह है कि जो कुछ भी कदम उठाया जाये वह सैनिक दृष्टि से ही उठाया जाये हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये तथा हमें चीन की शक्ति के संबंध में कोई भ्रांति भी नहीं होनी चाहिये उसे बहुत अधिक नहीं समझना चाहिये।

यह समझ लेना चाहिये कि चीनियों ने डर कर युद्ध विराम का प्रस्ताव किया है। वे भारतीय जवानों का सामना नहीं कर सकते हैं। नेफा में हमारी हार हमारे जवानों की हार नहीं है यह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फैंक एन्थनी]

गैर-सरकारी और खराब नेतृत्व की हार है। वहां हमने भयंकर गलतियां कीं। दूसरी ओर लद्दाख के युद्ध ने हमारे जवानों की वीरता में चार चांद लगा दिये हैं। यह असाधारण साहस और वीरता की कहानी है जो हमें समुचित शब्दों में नहीं बतायी गयी है। हमें यह भय अपने मन से निकाल देना चाहिये कि चीन की शक्ति बहुत अधिक है।

चीनी इस शां।त का उपयोग अपनी स्थिति को दृढ़ करने में लगे हुये हैं। उन्होंने अपने जासूसों द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी का लाभ उठाया है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

जहां तक असैनिक शासन का प्रश्न है उसमें आपातकालीन भावना पैदा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने शिक्षा मंत्रालय को यह लिखा कि हम अपने स्कूल में राष्ट्रीय छात्र सेना दल की स्थापना करना चाहते हैं इसका मुझे यह उत्तर मिला कि उनके पास पैसा नहीं है।

अन्त में म यह बता देना चाहता हूं कि शांति अहिंसा इत्यादि की बातें इस समय के उपयुक्त नहीं हैं। पहिले हमें युद्ध जीतना चाहिये तत्पश्चात् इस प्रकार की बातें करनी चाहियें।

श्री मुत्याल राव (महबूबनगर) : अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर महोदय ने आज अपने मोशन को पेश करते हुये जो विचार प्रकट किये है, मैं उन की पुरजोर ताईद करता हूं।

अभी हमारे किसी दोस्त ने कहा कि यहां से मेम्बर्ज को इस देश का दृष्टिकोण समझाने के लिये हर मुल्क में जाना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि मैं और मेरे चन्द साथी हाल ही में युनाइटिड नेशन्ज से वापिस आये है। आज युनाइटिड नेशन्ज में हिन्दुस्तान की बहुत इज्जत है। सिर्फ चन्द ही मुल्कों ने हमारी क्रिटिसिज्म की है और बाकी सब मुल्कों की ताईद हम लोगों को हासिल है और इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है।

मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि कल मेरी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई थी। १९५३ में जब मैं हैदराबाद स्टेट में एम० एल० ए० था, तो मैंने एन० सी० सी०, जिसको लोक सहायक सेना कहते है, कि ट्रेनिंग पाई थी और मैं ५०० लड़कों में बैस्ट आया। १९५६ में दिल्ली में हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई, उसमें भी मैं बैस्ट आया। मैंने वह ट्रेनिंग इसलिये ली थी कि मैं मुल्क के काम आऊं। आज वह दिन आ गया है और इसलिये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत चाहता हूं कि अपने मुल्क की खिदमत करने के लिय मैं सोल्जर बन कर फ्रंट पर जाऊं। अगर मेरे सोल्जर बनने में कोई कानूनी दिक्कत है, तो मैं अपनी पार्लियामेंट की सीट से भी रेजाइन करने के लिये तैयार हूं। इससे बढ़ कर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मेरे पास धन होता, तो मैं धन भी देता। लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरे आठ बच्चे भी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह मोशन पेश करते हुये बड़े ईमानदाराना ढंग से अपने विचार हाउस के सामने रखे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथी जितने भी कांग्रेस के मेम्बर हों या दूसरी पार्टी के मेम्बर हों, जितने भी नौजवान मेम्बर्स पार्लियामेंट के हों, वह भी हमारे साथ ज्वाइन हों और मुल्क की खिदमत करें।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : वस्तुतः युद्ध में किसी को भी ऐसे खतरनाक शत्रु का सामना नहीं करना पड़ा तो भी हमारे जवानों ने कठिन पर्वतों पर बर्बर शत्र का सामना बहुत जीवट के साथ किया हमारे सीमांतपर जो कुछ भी हुआ है उससे समस्त विश्व हिल उठा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान आपात में हमारे लोगों का सहयोग बहुत उल्लेखनीय रहा है। उस सहयोग के कारण ही चीनियों ने अपने अदूरदर्शी युद्ध के बारे में पुनः सोचने की आवश्यकता हुई होगी।

कूटनैतिक क्षेत्र में सरकार ने जो शांतिमय कार्यवाही की है। उसके लिये वह प्रशंसा की पात्र है। मुझे विश्वास है कि इसके शुभ परिणाम होंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, संकट के इन ऐतिहासिक क्षणों में जहां हमको फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है और अपनी वाणी से एक-एक शब्द तोल कर बोलने की आवश्यकता है वहां उतनी ही आवश्यकता इस बात की है कि हम निर्णय भी उतनी ही समझदारी और दूरदर्शिता से लें। और फिर देश के साथ हमारे निर्णय लेने का प्रश्न इस समय उपस्थित है, पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह पंचशील के पवित्र दस्तावजों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी वह देश अपने वादे पर न टिक सका। अब उस देश की ओर से हमारे सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव आया है। इस युद्ध विराम के प्रस्ताव पर परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता ने कई बार सरकार की नीति स्पष्ट करने का यत्न किया। ज्यों-ज्यों उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करने का यत्न किया, उतनी ही स्थिति अस्पष्ट होती चली गई। आज पहली बार प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है।

मुझे विश्वास है कि कोलम्बो के अन्दर जो कुछ तटस्थ देशों का सम्मेलन हो रहा है उसमें वह सारे राष्ट्र बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेंगे, विशेषकर वे राष्ट्र जिनकी विपत्ति के क्षणों में भारतवर्ष ने अपना कंधा लगाया है। उदाहरण के लिये इंडोनीशिया जैसा देश, जिसके स्वातंत्र युद्ध में भारतवर्ष का भी बहुत बड़ा हाथ था, बर्मा, जिसकी विपत्ति में हमने हथियार दिये थें, नेपाल, जिसको राणाओं के मुंह से निकालने के लिये, हमारी सरकार ने मदद भेजी थी, और लंका, जिस के प्रधान मंत्री की हत्या के पश्चात् जब वहां जनतंत्र डांवाडोल होने लगा था ऐसे समय में भारतवर्ष ने उसकी कमर पर हाथ रक्खा और साहस बंधाया था। उसी प्रकार घाना और कम्बोडिया आदि देशों के साथ भी हमारे संम्बन्ध रहे हैं। लेकिन चीन से भयभीत होकर अगर उनमें से किसी देश का मन किसी प्रकार की भी डांवाडोल स्थिति में हो तो भारत सरकार को उसे देखकर कोई निर्णय न लेना चाहिये अपितु जब कभी हम चीन के साथ निर्णय लेने के लिये जायें तो हमारे मस्तिष्कों में इस देश का पुराना इतिहास, इसके साथ-साथ इस देश की जनता, जिसने आज की राष्ट्रीय सरकार के साथ एकमत होकर अपने सहयोग का आश्वासन दिया है, हमारे देश के वह पवित्र प्रहरी, हमारी सेना के सैनिक, जो इस समय मोर्चों पर लड़ रहे हैं और साथ ही वे ६० देश हों जिन्होंने इस विपत्ति में हमें अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। हम कोई भी इस प्रकार का कमजोर निर्णय न लें जिस निर्णय का प्रभाव हमारे मनोबल पर विपरीत पड़े। इसीलिये इस प्रकार का निर्णय लेते समय हमें इन तमाम बातों के साथ बड़ी दूरदर्शिता की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हम एक बात और भी ध्यान में रक्खें आज ही प्रधान मंत्री ने अपने प्रातःकाल के भाषण में विश्व न्यायालय की चर्चा की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ दिन पहले इस देश के एक बड़े दूरदर्शी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भी ऐसा सुझाव दिया था। लेकिन परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता ने उस समय श्री जयप्रकाश नारायण के सुझाव का यह कह कर विरोध किया था कि जब एक देश हमारी धरती पर आक्रामक की स्थिति में बैठा हुआ है उस समय हम किसी के सामने समझौते के लिये अपना प्रस्ताव या समझौते के लिये अपना केस कैसे पेश कर सकते हैं ? यह बात तो समझ में आ सकती थी कि अगर चीन हमारी धरती को छोड़ कर हमारी सीमा से पार चला जाय, और हमारी सीमा से पार जाने के बाद उस के पास कुछ सीमा सम्बन्धी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दस्तावेज इस प्रकार के हों जिनके बल पर वह कहे कि इतना हिस्सा हमारा है और हम कहें कि नहीं इतना हिस्सा हमारा है, तो उस झगड़े को निपटारे के लिये विश्व न्यायालय को सौंप दिया जाय। यह बात तो बुद्धिमत्ता की कही जा सकती थी। लेकिन जब तक हमारी धरती पर आक्रामक बैठा हुआ है और वहां उसकी मिलिटरी और सैनिक हलचल जारी हैं, तब तक विश्व न्यायालय की चर्चा करना, मैं समझता हूं कोई दूरदर्शिता की बात नहीं कही जायेगी। वह भी ऐसे समय में जब कि सुरक्षा परिषद में कश्मीर के केस को देकर हम एक बहुत कड़वा अनुभव कर चुके हैं। इसलिये उसी प्रकार का कोई नया निर्णय लेते समय भी पुराने अनुभवों को ध्यान में रखें।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि इस आक्रमण से हमें थोड़ी चेतावनी भी मिली है, और वह चेतावनी यह है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के सम्बन्ध में सावधान रहें। विशेषकर उन देशों से जिनके साथ हमारे सीमा सम्बन्धी झगड़े हैं। सावधान रहें हम उन देशों से जिनकी राष्ट्र नीति और हमारी राष्ट्र नीति में कुछ भेद है, चाहे वह कम्युनिस्ट हों चाहे कम्यूनलिस्ट हों। कोई भी हों उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मैं चाहूंगा कि इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय हमारे प्रधान मंत्री एक बात का स्पष्टीकरण और भी करें। यह तो मैं नहीं कह सकता कि इस बात की कहां तक सही जाच कर पाया हूं, लेकिन जब गौहाटी में प्रधान मंत्री जी गये थे तब उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उसमें उनसे पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि पाकिस्तान और चीन का आपस में इस प्रकार का समझौता हुआ है कि असम को लेने के पश्चात् चीन उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना चाहता है? इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के जो शब्द मैंने पढ़े हैं व इस प्रकार हैं:-

> "मैं नहीं कह सकता कि चीन ने पाकिस्तान को असम का कुछ भाग देने की बात की है या नहीं।"

इन शब्दों से मुझे कुछ ऐसी ध्वनि आती दिखाई दी, कि भारत सरकार के पास कुछ डाक्यूमेंटरी प्रूफ इस प्रकार के हैं जिनके द्वारा यह बात सिद्ध होती हैं कि कोई अन्दरूनी समझौता हुआ जरूर है। अगर कोई इस प्रकार की बात हो तो इस सदन को वे अपने विश्वास में अवश्य लें।

अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए एक बात अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से हमारे पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री अपने स्थान से हटे हैं और एक और सुयोग्य व्यक्ति के हाथों में प्रधान मंत्री ने वह कमान दी है, तब से इस देश में छः सात व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिन्होंने एक आंदोलन (कम्पेन) शुरू किया हुआ है, और वे व्यक्ति भाषणों और समाचारपत्रों में कहते फिरते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिष्ठा भी खतरे में डाली है। लेकिन सच्चाई यह है वह पंडित जी की आड़ में अपने खतरे में पड़े व्यक्तित्व को बचाना चाहते हैं और पंडित जी का नाम लेते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विपत्ति-काल में सारा देश उनके पीछे है और सारा देश आज उनके आदेश को उसी प्रकार मानने के लिए तैयार है जिस प्रकार एक सैनिक अपने सेनापति के आदेश को मानने के लिये तैयार रहता है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने फिलासफर स्टेट्समैन से आज सोल्जर स्टेट्समैन का रूप धारण कर लिया है हमें प्रसन्नता है और यह देश के लिये सौभाग्य की भी बात है। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं उनका ध्यान अपने देश की एक विशेष परम्परा की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका हमारा इतिहास भी साक्षी है। महा कवि कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि रघुकुल की यह परम्परा थी कि

उनका जो निर्णय होता था जब तक उसकी कार्यरूप में परिणति नहीं हो जाती थी उस समय तक किसी को उसका पता नहीं चलता था। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है :

"मौनोस्मि गुह्यानाम्"

अर्थात् जितने भी रहस्य हैं उनमें सर्वोत्तम जो रहस्य मौन है वह मैं हूं। तो मैं चाहूंगा कि इन विपत्ति के क्षणों में अधिक वक्तव्य देने की अपनी परम्परा को वह कुछ कम कर दें।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी अधिक वक्तव्य नहीं देना चाहिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, २१ नवम्बर की तूफानी रात को जब पीकिंग से सीज फायर की सूचना मिली, उस सीज़ फायर की सूचना को भारतवर्ष के राजनीतिज्ञों ने किसी भी रूप में लिया हो, पर मैंने उसको एक इंटरवल की तरह समझा। मुझे उसमें कोई वास्तविकता या असलियत नहीं नजर आती। सीज़ फायर के बारे में बहुत से विद्वानों के बहुत से मत हैं। कुछ का कहना है कि मास्को के दबाव के कारण यह हुआ। कुछ का कहना है कि जो हमको अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा आदि मित्र राष्ट्रों से सहायता आयी उसके भय के कारण यह हुआ। कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि क्यूबा की परिस्थिति को चीन सरकार ने जैसा समझा था वह उसके विपरीत निकली इसलिये यह सीज फायर हुआ। कुछ लोगों का विचार है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से चीन सरकार को जो आशा थी वह निराशा में परिणत हो गयी, इसलिये यह सीज फायर हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय राष्ट्र की भावनाओं ने अपना बल दिखाया और जनता जातिवाद, प्रांत वाद और भाषावाद को भुलाकर राष्ट्र के बचाव के कार्य में एक हो कर पूरी शक्ति के साथ जुट गयी, इस से चीन को बहुत गहरी चोट पहुंची इसलिये सीज फायर किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि चीन बहुत दिनों तक लम्बी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिये सीज फायर हुआ। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जाड़ में चीन कुछ दिनों के लिये संग्राम को रोक देना चाहता है, इसलिये सीज फायर किया गया है। कुछ लोग यह कहते हैं कि भारतवर्ष को जो आज विदेशों से सहायता मिल रही है उसको दूसरा रूप देने के लिये चीन ने ऐसा किया है। ये तमाम चीजें अपनी-अपनी जगह पर हैं, पर मैं सोचता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा वास्तविकता यह है कि कम्युनिस्ट लोगों की तरह चीन का भी यह विश्वास है कि लड़ो, रुको, उसके बाद मजबूत बनो, दुश्मन को क्यों धोखा दो, सेना को तैयार करो और फिर आगे बढ़ो इसलिये यह सीज फायर हुआ है। सीज फायर का कोई भी कारण हो सकता है लेकिन मैं उसका यही कारण समझा हूं। दूसरी एक बात और भी हो सकती है कि चीन ने भारत का जो कुछ भी हिस्सा ले लिया है उसमें यातायात के साधन कम हैं जिसकी वजह से चीन को आगे बढ़ना रोकना पड़ा है और उसने सीज फायर किया है। भारत वर्ष के प्रति भाई चारे की भावना से चीन ने सीज फायर नहीं किया है। भारतवर्ष ने चीन को हर तरह से सहायता दी। चीन सरकार को सबसे पहले रिकागनीशन दिया। यू० एन० ओ० में उसको मान्यता दिलाने की बहुत कोशिश की, और अपने पांच हजार नौजवानों की आहुति दी। उसका चीन ने यह जवाब दिया कि उसने हमारे देश की इतनी भूमि पर कब्जा कर लिया। इससे स्पष्ट है कि हमारे प्रति मित्रता की भावना से प्रेरित हो कर चीन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस सीज फायर में कोई भी वास्तविकता नहीं है और न इससे दोस्ती का कोई ताल्लुक है। जो ऐसा समझता है वह धोखा खायेगा। हमारा पुराना तजुरबा इस बात का साक्षी है। और हमारे प्रधान मंत्री जी

[श्री मौर्य]

श्री जवाहरलाल नेहरू को हम सब से इसका ज्यादा तजुरबा है । उन्होंने चीन की दोस्ती पर बहुत भरोसा किया था ।

हमने चीन पर तो इतना भरोसा किया, जिससे हमारी संस्कृति नहीं मिलती, पर हमने उन लोगों का विश्वास नहीं किया जिनके और हमारे बाप दादा एक थे । लेकिन आज जो हम से अलाहिदा हो गये हैं । पाकिस्तान के लोग जो आज हमसे अलग हो गये हैं । उनकी सीमा पर हमने फौजें रखीं, ठीक है, रखना चाहिये था । लेकिन चीन की सीमा पर हमने ऐसा नहीं किया, उस चीन की सीमा पर जिसका हमारा कल्चर एक नहीं है, जिसकी हमारी सभ्यता एक नहीं रही । चीन की तरफ हमने दोस्ती का हाथ कितने विश्वास के साथ बढ़ाया, जिसका आज यह नतीजा हमें देखने को मिला ।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा । आज इस सीज फायर की आड़ में चीन एक मुंसिफ की हैसियत में बैठ कर हम से इस प्रकार सवाल करता है जैसे कि हम मुलजिम हों । भारत सरकार ने इन सवालों का जवाब दे दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि उनका जवाब देना भारतवर्ष के लिये अपमानजनक है । आज चीन हमसे इस तरह सवाल करता है जैसे एक जज एक मुल्जिम से सवाल करता है कि हां या ना में जवाब दो ।

मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि हमको चाहिये कि हम चीन की इस चुनौती को, जो कि भारतवर्ष के लिये ही नहीं संसार के सारे शांतिप्रिय राष्ट्रों के लिये एक चुनौती है, स्वीकार करें और उसका सामना करें । आज देश की ४१ करोड़ जनता अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर देश की रक्षा करने के लिये तैयार है । आज सरकार को भी चाहिये कि वह कम से कम खर्च करके और भी अधिक जनता का विश्वास प्राप्त करे । आज देश में जो भावना है उससे चीन तो क्या चीन के दस-गुनी बड़ी शक्ति का भी हम मुकाबिला कर सकते हैं । यह देश के सम्मान का सवाल है । हमको चीन की इस चुनौती का पूरी शक्ति के साथ मुकाबला करना चाहिये । यदि ऐसा करने में हमारे देश के एक दो करोड़ लोग काम भी आ जायें तो कोई चिन्ता की बात नहीं । फिर भी ४० करोड़ लोग बाकी बचे रहेंगे । पर इससे देश के सम्मान की रक्षा हो जायेगी, नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सदा चीन से डरती रहेंगी । हमको इस समय जरा भी बुजदिली नहीं दिखानी चाहिये ।

हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यह लड़ाई लम्बी चलेगी । जब ऐसी स्थिति है तो मेरा सुझाव है कि हमको अपने स्कूल और कालिजों में पढ़ने वालों विद्यार्थियों को, जो १७ साल से १९ साल तक की उम्र के हों, अनिवार्य मिलिटरी शिक्षा देनी चाहिये । हम शांति प्रेमी लोग रहे हैं और हमने शांति का पाठ सीखा है लेकिन जब हमको भारत माता की रक्षा का पाठ सीखना है । हमको उसके लिये हर प्रकार का प्रयत्न करना पड़ेगा ।

आज पंडित नेहरू और भारत इन दो शब्दों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि पंडित नेहरू ही भारत है और भारत पंडित नेहरू हैं । इन शब्दों के साथ मैं श्री नेहरू का नहीं भारत का, भारत का नहीं श्री नेहरू का, क्योंकि आज इन शब्दों में कोई फर्क नहीं है, अपनी पूरी शक्ति के साथ समर्थन करता हूं ।

†श्री मु० इस्माइल (मंजरी) : चीनियों ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव किया है वह प्रचार का हथकंडा और धोखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने सुझाव दिया है कि हमारी सीमा पर निरस्वामिक भूमि ("नो मैन्स लैंड") बनाई जाय। ऐसा करने से हमारी भूमि निरन्तर खतरे में रहेगी। यह सुझाव हमारी सुरक्षा एवं स्थिरता के लिये भी खतरनाक है।

चीनी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उत्तर में हमारी कोई सीमा नहीं थी। दूसरे वे चाहते हैं कि हिमालय का जल विभाजन हमारी सीमा न रहे। इन दो चीजों से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

हमें भूतकाल के विषय में अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिये। जो कुछ हो गया सो हो गया। संसद ने प्रधान मंत्री और उनकी सरकार में विश्वास प्रकट किया है। यदि संसद सदस्य कोई जानकारी चाहते हैं तो सरकार की आलोचना के लिये नहीं, परन्तु इस लिये कि वे लोगों को युद्ध की स्थिति ठीक प्रकार से समझा सकें।

इस समय देश में एकता की भावना पैदा हो गई। इस एकता के बल पर हम चीनियों पर शीघ्र ही विजय पायेंगे।

पाकिस्तान यदि स्वयं इस बात को समझ कर कि चीन से उसे भी खतरा है। हमारे साथ सहयोग दे तो अच्छा है, अपितु भारत के लोग स्वयं ही चीन का मुकाबला करें और विजय प्राप्त करेंगे।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का बहुत थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि अभी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोलना है।

सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १४ नवम्बर को इसी हाउस में आपके आदेश पर हम सब ने खड़े होकर चीनी आक्रमण के बारे में अपनी भावना को प्रकट किया था। हमने यह दृढ़ निश्चय किया था कि चाइना ने भारत की जो भी टैरीटरी दबाई है, निश्चित रूप से वह सारी की सारी उससे वापिस ली जायेगी। यदि अब सरकार उस प्रस्ताव के साथ कोई और शर्त जोड़ती है, तो उसका परिणाम यह होगा कि आज जिस प्रकार का टेम्पो देश में बना हुआ है जिस प्रकार की सद्भावना आज सरकार के साथ है, उनके लिये एक भारी अन्देशा पैदा हो जायेगा।

सरकार का बार-बार यह सोचना, यह सन्देह प्रकट करना कि हम चाइना या संसार की किसी भी शक्ति के साथ लड़ नहीं सकते, हम में कोई कमजोरी है, मैं समझता हूं इस भावना का आना ही बड़ी भारी कमजोरी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हम डिटरमिनेशन निश्चित भावना के साथ खड़े हो जायें, तो भारत को इतनी बड़ी जन-संख्या का इतना बड़ा मनोबल आज सरकार के साथ है, उस के द्वारा हम संसार की किसी भी शक्ति को पीछे धकेल देने में समर्थ हैं।

एंग्लो-एमेरेकिन्ज ने जिस प्रकार के वातावरण का आरम्भ में निर्माण किया था उसके लिये मैंने उन्हें इसी सदन में धन्यवाद दिया था। पर उसके खिलाफ आज मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह कोई सौदा नहीं है, अथवा कोई रोजगार भी नहीं है, बल्कि आज सारे संसार की शक्तियां दो भागों में विभाजित हैं—एक ओर तो कम्यूनिस्ट भावना के देश हैं और दूसरी ओर वे देश हैं, जो कि प्रजातांत्रिक शासन में विश्वास करते हैं। अतः अमरीका, इंग्लैंड और उनके दूसरे एलाइड कंट्रीज का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वे हमारे देश के साथ आयें और कंधे से कंधा लगा कर मदद करें, अगर वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं। आज यह सोचना गलत होगा कि यह लड़ाई चाइना और हिन्दुस्तान

[श्री विशनचन्द्र सेठ]

के बीच है। यह लड़ाई संसार की दो विचार-धाराओं में चल रही है। ऐसी स्थिति में उन का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वे किसी प्रकार का सौदा न करें---(मैं किसी चीज का नाम नहीं लेना चाहता)-और न कोई ऐसी शर्त लगायें कि पहले यह तय करो, फिर हम मदद करेंगे। ईमानदारी की बात यह है कि अगर वे संसार में प्रजातांत्रिक शासन को जीवित रखना चाहते हैं, तो उन्हें भारत को अनकन्डीशनल स्पोर्ट देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने ऐसा ही किया है।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : नहीं, नहीं। माननीय सदस्य कागज की बात न कहें। मैं अन्दर की बात बता रहा हूं।

मैं पहले भी माननीय प्रधान मंत्री जी से यह अपील कर चुका हूं---जिसकी ओर उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं कि दलाई लामा की सरकार को फौरन मान्यता दी जाय और उनके के केस को यू० एन० ओ० में भेजा जाये। चाइना के लिये इस समय हमें भी एक नया खटराग पैदा करना चाहिये। लेकिन हमारी सरकार ऐसे ही बैठी है। इससे क्या होगा ? हमारी सरकार की यह भावना होनी चाहिये कि ऐसी नीति अपनाई जाये कि चाइना को भी पता चले कि कोई उसके मुकाबले पर है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जिस तरह से भी हो तिब्बत के लोग जब चाइनीज के साथ नहीं हैं। वहां की जन भावना चाइनीज के साथ नहीं है, तो आपके पास इससे ज्यादा सुनहरा मौका और कौन सा होगा ? इसलिये आपको समय का लाभ उठाना चाहिये।

अन्त में केवल एक ही चीज क्यूबा की मिसाल देना चाहता हूं। अगर अमरीका ने एक दम सारे क्यूबा कें एरिया को घेर न लिया होता तो निश्चित रूप से आज संसार के सामने यह परिस्थिति न होती। अमरीका ने संसार के सामने एक बड़ी भारी एग्जाम्पल पैदा की है, जो आज से कुछ ही दिन पहले की बात है। ठीक उसी तरह से हमारे देश को भी चाइना का मुकाबला करना चाहियें। इस मामले में बार-बार अजीब-अजीब बातें सोचने से हमारे देश के मोराल पर बुरा असर पड़ता है।

†**श्री रंगाः** (चित्तूर) : अब तो चीनियों के इरादे स्पष्ट हैं। इस समय प्रधान मंत्री को देश को यह ललकार देनी चाहिए थी कि हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चीनियों के शांति के प्रस्तावों की ओर ध्यान नही देना चाहिए। आज प्रातः प्रधान मंत्री जी का भाषण निराशाजनक रहा है। किन्तु आशा है कि एक दिन अवश्य आएगा जब प्रधान मंत्री जी जनता को उसके प्रयत्नों को दुगुना कर के आक्रांता को निकाल फेंकने के लिए अवश्य ललकारेंगे।

हमारी सरकार को चाहिए कि वह साम्यवादी और साम्राज्यवादी आक्रमण ने विश्व के प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए मित्र देशों से बड़े पैमाने पर सहाता ले। आज प्रधान मंत्री जी ने इस मामले को हेग न्यायालय में ले जाने का जो सुझाव दिया है वह बहुत देर से दिया है। यह सुझाव बहुत पहले दिया जाना चाहिए था। यह ठीक बात है कि हम इस सुझाव पर तब अमल करेंगे जब युद्ध का निर्णय न हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहले हमें चीनियों को अपने देशों से बाहर रखना होगा; केवल तभी हम हेग न्यायालय में जाने की बात सोच सकते हैं जिससे कि हम सीमा के मामले में शांति से रह सकें।

यह समय इस बात के लिए उचित है कि दलाईलामा को यहां पर अपनी जनता के प्रधान के रूप में स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए। तिब्बत को न केवल वहां के लोगों के प्रयत्नों से आजाद करना चाहिए, परन्तु उन सब लोगों को अपनी नैतिक और भौतिक सहायता भी देनी चाहिए जिन को प्रजातंत्र, शांति और भद्रता से प्रेम हो।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जब से हम युद्ध में लगे हुए हैं तब से देश में युद्ध सम्बन्धी नीति के विशेषज्ञों की कमी नहीं रही है। मेरे पास इस सम्बन्ध में कई पत्र आते हैं। मैं युद्ध, सम्बन्धी मामलों का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, परन्तु मैं ने इस के सम्बन्ध में कुछ पढ़ा है, पिछले कुछ युद्धों को समझा है। बिल्कुल सैनिक मामलों में भी तो विशेषैज्ञों की राय लागू होनी चाहिए। हम युद्ध को अलैहदा तौर से नहीं सोच सकते। कुछ राजनैतिक दलों के महत्वपूर्ण सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यह युद्ध है और कुछ नहीं है। यह बहुत अजीब वक्तव्य है। बलवान होना एक बात है और इसे अलैहदा से सोचना और बात है। तब भी किसी ने ऐसा किया है और न कोई ऐसा करेगा। सैनिक मामलों के प्रसिद्ध जर्मन लेखक कलौजविप्स ने कहा कि युद्ध राजनीतिक का ही एक रूप है; युद्ध का सेना के अतिरिक्त प्रसारण से भी काफी सम्बन्ध है। अफ्रीका और एशिया के सभी देशों में चीन अपने मामले के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए लोगों को क्यों भेज रहा है। यह युद्ध से भिन्न बात है, परन्तु युद्ध से सम्बन्ध रखती है। चीन इसलिए उन देशों को अपने लोग भेजता है। क्योंकि वे कहते हैं वह उन्हें महत्वपूर्ण समझता है।

किसी ने मेरे से पूछा कि आप ने कोलम्बो को प्रतिनिधि क्यों भेजा? मैंने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, परन्तु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वहां गए। उन्होंने मेरे से पूछा और मैं ने कहा "निश्चय ही, वहां जाना आप पर निर्भर है", क्योंकि मुझे यकीन था कि यदि इस से लाभ न भी हो, हानि भी होगी। कुछ लाभ ही होगा। इस से विदेशी मुद्रा का भी प्रश्न उठता है सम्भवतः और किसी हमारे समर्थक से अधिकतर लाभदायक सिद्ध होंगे। सारी बात यह है कि कौन किस के साथ अच्छी तरह से बात कर सकता है। मान लीजिए कि मुझे अफ्रीका में कोई व्यक्ति भेजना है। तो वहां में ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो अफ्रीकी लोगों या देश से अच्छी तरह से सम्पर्क बना सकें। यदि रूस को मुझे कोई व्यक्ति भेजना होगा तो में ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जिस का वहां कुछ प्रभाव हो। प्रो० रंगा को वहां भेजने से मामला खराब हो जाएगा। जब आप लड़ भी रहे हों तो भी यह देखना होता है कि किस देश को कौन सा व्यक्ति भेजा जाना चाहिये। दूसरे महायुद्ध मैं प्रचार में कूटनीति और राजनीति सें हमेशा काम किया है। मैं यह सब इसलिए कहता हूं कि यह घटना कि हम बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ नष्ट कर दें और युद्ध जीतलें इस का कोई मतलब नहीं है। जो भी हम कार्यवाही करे उस के नतीजे के सम्बन्ध में अवश्य सोचना है। नतीजों से शत्रुओं का ही नहीं बल्कि हमें भी हानि हो सकती है।

श्री चर्चिल का भी जिक्र आया था। वह युद्धकाल में बहुत अच्छे नेता थे। 'आप उसकी शक्ति की प्रशंसा करते हैं। उन की शक्ति के पीछे कूटनीति, राजनीति आदि में उनका काफी तजुर्बा भी था। वह भी आप को याद रखना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मेरा ख्याल है कि चीन-भारत विवाद पर अधिक पत्र-व्यवहार होने के कारण माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम है। इस वक्तव्य में जो आया है, जिसे उन्होंने केवल जारी किया था और जो आज प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतियां शायद संसद्-पुस्तकालय में रखी गई हैं, दस या बारह फुलस्केप टाइप किये हुए पन्ने हैं। जब तक हम इसे समाप्त करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। इसी कारण कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। मुझे खेद है कि हमारे उत्तर भी काफी लम्बे रहे हैं।

हमें इस मामले पर राजनयिक ढंग से कार्यवाही करनी है क्योंकि उनसे कुछ कहते हुए हम संसार से कुछ कहते हैं। प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य सोचते हैं कि क्योंकि वे और हम सचाई जानते हैं, इसलिए संसार को भी सचाई निश्चित रूप से जाननी चाहिये और हमें केवल यह करना है कि हम उन्हें बता दें। यह ठीक नहीं है हमें उन्हें वह विशेष प्रसंग बताना होता है, बताना होता है कि हम उचित और ठीक रवैया अपना रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे या चीन के वक्तव्यों को पूरी तरह नहीं पढ़ेगा। वे तो मोटी बातें जानते हैं। हो सकता है कि वे चीन के प्रति कहे विचार रखते हों और इस कारण हम जो भी कहें मान लें। अथवा, हो सकता है कि वे हमारे प्रति अच्छे विचार रखते हों, अतः हम जो भी कहें वह वे मान लेंगे। परन्तु अधिकतर ऐसी बात नहीं होती। अतः उन्हें औचित्य आदि से सन्तुष्ट करना होता है। यहां ही राजनीतिक तथा राजनियक दृष्टि की बात आती है। यह स्पष्ट है कि हमें बहुत ही कठिन स्थिति के बारे में कार्यवाही करनी है। चीन के बारे में आप के चाहे जो विचार हों, उनके अतिरिक्त चीन एक बहुत बड़ा और शक्तिशाशी देश है। अतः यह गोआ, आदि जैसी कार्यवाही करने का मामला नहीं है।

मैं ने खूब विचारा है कि और मुझे विश्वास है कि चीन इस मामले में मनमानी नहीं कर सकता और हम इस में अपनी कार्यवाही करेंगे। इसके अनेक कारण हैं। यदि हम अपनी शन्ति के बल पर चीनी सीमा के पार कार्यवाही करें, तो हमारी स्थिति कमजोर होगी और उनकी स्थिति जोरदार होगी। यह प्रश्न इस बात का है कि वे कैसे और कहां और किस लिए कार्य करते हैं।

†**श्री रंगा** : वह अतिक्रमणकारी हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिल्कुल ठीक है। अधिकाधिक व्यक्ति यह बात महसूस कर रहे हैं। जैसा कि श्री खाडिलकर ने कहा है, यह झगड़ा कुछ क्षेत्र का ही झगड़ा नहीं है। हां इसमें राज्यक्षेत्र अवश्य शामिल है, परन्तु इसमें निश्चित ही कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। चीन ने इस प्रश्न को कुछ विश्वासघाती ढंग से लिया है। मान लीजिये उन्होंने कुछ समय पहिले कहा होता कि यह उनका राज्य क्षेत्र है और हमने कह दिया होता कि नहीं यह तुम्हारा राज्यक्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा "ठीक है।" युद्ध के अतिरिक्त, हम इसका निर्णय कैसे करें? क्या हम उनसे "नहीं" कह देते, हम इस बारे में तुमसे बात नहीं करेंगे। स्पष्ट है, यदि ऐसा होता है और दो देशों के बींच किसी राज्य क्षेत्र के बारे में झगड़ा हो, तो इसका निर्णय शांतिपूर्ण ढंग से किया जायेगा। साधारण रूप में कोई युद्ध नहीं करता, कभी

†मूल अंग्रेजी में

हो सकता है कि कोई युद्ध करे। परन्तु उन्होंने इस प्रश्न को इस तरह उठाने के बजाये, हमें गलत नक्शे दिखाये और बाद में अकसाई चिन सड़क बनाई और कुछ तिब्बत दबा लिया। यह बहुत ही अनुचित प्रक्रिया है और इससे बुरी विचारधारा व्यक्त होती है।

अतः यह उस क्षेत्र का ही प्रश्न नहीं है जहां चीन ने अतिक्रमण किया अपितु उससे बड़ा प्रश्न है। हालांकि राज्यक्षेत्र का प्रश्न भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका मुकाबला पूरी शक्ति से करना भी हमारे लिए एक बड़ा तर्क है। परन्तु इस में निश्चय ही इससे अधिक कुछ बात और है। माननीय सदस्यों ने **रघुवंश** आदि से कुछ श्लोक पढ़े थे। हिमालय भारत का अंग है, यह प्रत्येक भारतीय जानता है। हजारों वर्षों से हमारे साहित्य में हिमालय का उल्लेख है। वहां हमारी संस्कृति है। वहां प्रत्येक बात है। अतः यह हम से अधिक मिलता है, बजाय इस के कि यह हमारा एक राज्य क्षेत्र है।

शेष संसार को हिमालय से हमारे भावात्मिक संबन्धों से कोई वास्ता नहीं है। परन्तु उनका इससे बड़ा सम्बन्ध है कि चीन ने विभिन्न मामलों में क्या रवैया अपनाया है। यह सर्व विदित है। यह क्या है, यह बताना मेरा काम नहीं है। परन्तु साम्यवादी देश रूस और चीन के बीच कोई अधिक अच्छे सम्बन्ध नहीं है। संसार में बड़े बड़े प्रश्न हैं। बड़े प्रश्नों में से एक बड़ा प्रश्न रूस और चीन के सम्बन्ध का है। यह एक विश्व का प्रश्न है। अतः यदि कोई राजनीति या कूटनीति में पड़ता है, तो उसे यह स्थिति अपने सामने रखनी पड़ती है। यदि कोई युद्ध में पड़ता है, तो उसे यह बात अपने सामने रखनी पड़ती है। श्री रंगा जो सुझाव देते है, वह केवल हानिकारक ही नहीं अपितु निश्चित रूप से हानिकारक है। उन्होंने यह बात अभी नहीं समझी है और मैं उन्हें यह बात नहीं समझा सकता . . . . **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : (जालोर) : हरिमेन का उल्लेख करिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने मुझ से पूछा था कि मैं ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं ने चीन को साम्यवादी चीन कहा था। हां, चीन साम्यवादी है। परन्तु वह एक अद्भुत प्रकार का साम्यवादी बन रहा है जिसे अन्य साम्यवादी होना भी हानिकारक समझते है और यदि आप उन सबको एक साथ रखे और बेकार में अपना विरोध बढ़ायें, तो यह अच्छी बात नहीं है।

मैं ने आरम्भ में कहा था कि श्री एन्थनी ने हमारे सैनिकों और उनके साहस आदि के बारे में क्या कहा है। निश्चय ही उस पर यहां किसी को सन्देह नहीं है। दुर्भाग्यवश, इस कारण कि यह घटना इस प्रकार हुई है और यह विचार बन गया है कि भारतीय सेना पर पहाड़ टूट पड़ा है। मैं नहीं समझता कि यह सही विचार है। निस्सन्देह, पराजय हुई है। हमें सचाई नहीं छिपानी चाहिये। परन्तु पराजय के विभिन्न कारण हैं। कि माननीय सदस्य चाहते थे कि इसकी जांच की जाय। निस्सन्देह, हम इसकी विभागीय जांच कर रहे हैं। हम दूसरी जांच कर सकते हैं और अधिकाधिक बातें सामने आयेंगी। परन्तु तथ्य काफी स्पष्ट है।

एक छोटी बात यह है, हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें सैनिकों को समुद्र तल से लगभग १४,००० फुट की ऊंचाई पर सैनिक जल्दी से भेजने पड़े। साधारणतया, जल वायु के अनुकूल

---

†मूल अंग्रेजी में

बनने में कम से कम तीन सप्ताह लगते हैं ; अन्यथा यदि किसी व्यक्ति को एकदम भेजा जाता है, तो उसमें केवल ३० प्रतिशत शक्ति रह जाती है। हथियारों, कपड़ों और खाद्य के बारे में यह सारी बात गलत है। हां, यदि उनके पास अच्छे हथियार होते, तो व निश्चय ही अच्छा काम करते। अब हमने उन्हें उत्तम हथियार दे दिये है, तो उनमें से अनेक अपने पुराने हथियारों को अधिक पसन्द करते है क्यों कि वे उनके आदि है। हल्के हैं और नये हथियार भारी है। विशेषज्ञों का मत है कि .३०३ की राइफलें उन स्थितियों में ठीक हैं। हो सकता है विचारों में विभिन्नता हो। परन्तु यह विचार कुछ सुप्रसिद्ध विदेशियों के हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : २२ अक्तूबर को बी० बी० सी० ने हमारे कुछ सेना अधिकारियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि नेफा में जो बन्दूकें प्रयोग की गई थीं, वे वह थीं जो दूसरी लड़ाई की बची हुई थीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** संभव है कि कुछ अधिकारियों ने एक बात कही हो और अन्य अधिकारियों ने दूसरी बात कही हो।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ माननीय सदस्य मृदु तथा मित्रतापूर्ण उल्लेखों पर गरम क्यों हो जाते हैं।

मैं कह रहा था कि हमारी पराज्यों का एक मुख्य कारण चीनी सेना की विशेष ट्रेनिंग और ढंग का था जो हमने कुछ वर्ष पहिले कोरिया के युद्ध में देखा था। वहां अमरीका के बहुत अच्छे सैनिक, जिनके पास नवीनतम हथियार थे उन लोगों द्वारा दबा दिये गये जिनके पास मामूली हथियार थे लेकिन जिन्होंने दूसरी तरकीब से काम लिया। यह पूछा जा सकता है कि हम उसके लिए क्यों तैयार न थे। मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता। इस प्रकार के मामले में शीघ्र सारी सेना की ट्रेनिग बदलना आसान नहीं है। निश्चय ही उससे हमें लाभ हुआ है और हम कम से कम सेना के कुछ दलों को इस विशेष ढंग की ट्रनिंग देंगे।

श्री राम सेवक यादव : आज सारे लोग न जाने कहां से आ गये है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाईट आफ आर्डर पीछे होगा, यह दूसरा प्वाईट आफ आर्डर था। लेकिन आपने जो कहा, क्या वह आपके लिये उचित था ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : यह बात मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि आज हाउस किन कठिन परिस्थितियों में यहां पर विचार कर रहा है ? जरा सोचिये तो।

अध्यक्ष महोदय : उनको बन्द करने की आप इजाजत तो दें। मैं क्या करूं अगर हर एक मेम्बर उसी में शामिल हो जाय तो किस को बन्द किया जा सकता है ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : कल आप ही ने कहा था कि श्री मनी राम बागड़ी को इस तरह से हंस कर एनकरेजमेंट नहीं देना चाहिये। आप स्वयम् सोचिये कि हम बड़ी संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहे है। उसमें यह हंसी कहां तक ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन से कहा, किसी और से तो नहीं कहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : यहां सब के सब एक साथ बोल उठते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक सदस्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है बशर्ते कि माननीय मंत्री उससे सहमत हों। यदि वह सहमत न हों, तो, शायद माननीय सदस्य को बैठना पड़ेगा और मैं अन्त में उन्हें अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय यहां यह परेशानी आती है। आज देश पर जो संकट है, आज जो हम इन परिस्थितियों में है, उन परिस्थितियों में ला कर डालने वाला कौन है? किस ने ला कर डाला है? आजकी सरकार ने। आज इस सरकार के लिये जिम्मेदार कौन है?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री मौर्य : कम से कम सरकार के लोगों को जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिये इन लोगों को। खास कर इस मौके पर जब कि दुनियां भर की आखें हमारी तरफ लगी हुई हैं। हम जानना चाहते है कि कौन जिम्मेदार है इस परिस्थिति के लिये।

अध्यक्ष महोदय : जो आप कह रहे है उस को भी दुनियां के लोग देख रहे हैं। आप को और हर एक को चाहियें, किसी तरफ भी वह बैठा हो, कि इस जिम्मेदारी को महसूस करे।

श्री मौर्य : हम उस जिम्मेदारी को समझ कर ही बोलना चाहते है, हम इन परिस्थितियों को समझ रहे है।

†**श्री राम सेवक यादव:** मेरे औचित्य प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह औचित्य का क्या प्रश्न है।

श्री राम सेवक यादव : जब बार बार इधर से कोई सवाल पूछा जाता है, कोई भी इंटरप्शन हो सकता है, कोई सवाल पूछा जा सकता है, तब यह आखिर क्या तरीका है कि "नहीं नहीं" अगर आप इस को नहीं रोक सकते तो कैसे कार्रवाई चलेगी?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्वाईंट आफ आर्डर का क्या जवाब दूं?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय मैं इसके सम्बन्ध में आप की व्यवस्था चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह व्यवस्था आप को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। मगर आपने कोई प्वाईंट आफ आर्डर नहीं उठाया है। अब आप आराम से सुनिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसी विषय के बारे में बोलते रहना कठिन होता है। जब कुछ माननीय सदस्य लगातार हस्तक्षेप करें, उत्तेजित हों और मुझे बोलने में बाधा डालते रहें।

मैं ने सभा के सामने एक कारण रखा था जिसे सब विशेषज्ञ जिन्हें मैं जानता हूं, भारतीय या विदेशी मुख्य कारण जो प्रमाणित हो चुका हैं। अमरीकी सेना, कोरिया में, सर्वोत्तम हथियारों सर्वोत्तम लोगों आदि के बावजूद, कठिनाई में पड़ गई थी, क्योंकि दूसरे पक्ष नें विचित्र ढंग, आधे गुरीला, आधे सैनिक अपनाये। इस के बारे में पुस्तकें लिखी गई हैं? मैंने कहा कि वर्तमान सेना को भी मलाया आदि में भिन्न तरीके अपनाने वाले जापानियों के मुकाबले में इसी

---

†मल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रकार पीछे हटना पड़ा था। दुर्भाग्यवश हमारी सेना को इन विशिष्ट तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। यह प्रशिक्षण दिया जा सकता है और दिया जाएगा। यह विवादास्पद बात नहीं, सरल बात हैं विश्वासनोय है, श्री फ्रैंक एन्थनी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि कोई भी यह नहीं समझे कि हमारे सैनिक या लड़ाक जवान उत्साह, योग्यता या वीरता में कम हैं। मुझे इसका भरोसा है। यह मेरा ही मत नहीं, अन्यत्र सेवाओं का ज्ञान रखने वाले लोगों का भी यही मत रहा है।

मैं तेजपुर के आगे के क्षेत्रों में गया था। मैंने उन लोगों को खाइयों या जहां वे थे वहां देखा वे बहुत बढ़िया थे,तनिक भी निराश नहीं थे; यद्यपि वहां की घटनाओं से यहां के कुछ लोग निराश थे।

अतः मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि नेफा और लद्दाख दोनों स्थानों पर हमारी सेनाओं का बड़ा ठोस दिल है। श्री ऐंथनी की यह बात भी ठीक है कि लद्दाख में उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई की है। नेफा में भी, सब जगह नहीं, कुछ भागों में उन्होंने बहुत बढ़िया लड़ाई की है।

गुप्त बातों का पता लगाने का कुछ उल्लेख किया गया है। इस का अनूमान लगाना कठिन है, किन्तु मैं समझता हूं कि कुल मिला कर हमारी गुप्तचर सेवा प्रथम श्रेणी की है।

†**श्री रंगा :** सी ला में हमें बहुत बुरा अनुभव है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे वहां की घटनाओं के बारे में कुछ उत्तम ज्ञान है। हम अपनी गुप्तचर सेवा को बड़े देशों की गुप्तचर सेवा से तुलना नहीं करते जिनका चारों ओर व्यापक जाल फैलाया होता है। वे इस पर भारत के कुल राजस्व से अधिक खर्च करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, न ही करना चाहते हैं कि सारा धन इस प्रकार खर्च करें। किन्तु अपने साधनों के अनुसार हमारी गुप्तचर सेवा अच्छी है। हो सकता है कि श्री रंगा मेरे इस अनुभव से सहमत न हों।

†**श्री रंगा :** हम सहमत नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरु : अब यह उत्तम हो सकती है और होनी चाहिये—यह भिन्न बात है।

मैं प्रसन्न हूं कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि हमें अपनी किसी गुट में शामिल न होने की नीति को नहीं बदलना चाहिये। किन्तु शायद उनके दल के एक सदस्य ने इसके प्रतिकूल बात कही है। नहीं मुझे खेद है, वह सदस्य स्वतंत्र पार्टी के थे जिन्होंने इस बात का विरोध करके यह चाहा कि हम सैनिक गुट आदि में शामिल हो जाएं, जिस से हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता ऐसा मैं समझता हूं और श्री द्विवेदी भी ऐंसा ही समझते हैं, बल्कि इससे कुछ हानि होगी। जिस नीति में आप विश्वास रखते हों उसे हालात के दबाव में आकर बदलना ठीक नहीं होता, विशेष कर जब कि अन्य पक्ष को, जैसा कि आप भली भांति समझ सकते हैं बहुत उत्तम परिणाम नहीं मिल रहे। मुझे इस बात का पक्का यकीन है और मुझे ऐसी प्रसन्नता है कि श्री द्विवेदी भी इस बात में विश्वास रखते हैं।

श्री द्विवेदी ने १५० करोड़ रुपये की कोई बात की है, जिसें मैं समझ नहीं सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मुझे विश्वस्तसूत्रों से पता चला है कि १५० करोड़ रुपये की हमारी सामग्री नष्ट हो गई है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ये आंकड़े कल्पनातीत हैं, अतः किसी व्यक्ति को समझने में गल्ती हुई है ।

दो या तीन मुख्य बातें हैं । एक है कि कुछ माननीय सदस्य यह नहीं मानते कि ८ सितम्बर की लाइन मानी जाये । सभा को याद होगा कि यह तिथि दो महीनों से बराबर पेश की गई है । पहले भी सभा में बताया गया था और मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक है । एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि तिथि १५ अगस्त, १९४७ होनी चाहिये । वास्तव में वह तिथि बहुत लाभदायक नहीं । निस्संदेह प्रश्न यह है कि तिथि को कौन सी रेखा थी, ऐसी बात नहीं कि आप ने कोई निश्चित पक्की रेखा बनाई हो और आप उस पर दृढ़ रहे हों ।

†**श्री राम सेवक यादव :** सब कुछ स्पष्ट है किन्तु ८ सितम्बर, १९६२ या ७ नवम्बर, ५७ सपष्ट नहीं । मानचित्रों में सब कुछ स्पष्ट है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं तर्क में नहीं पड़ना चाहता किन्तु यह कहूंगा कि १९४७ का मानचित्र सब लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

†**श्री प्रिय गुप्ता** (कटिहार) : केवल चीन ने नहीं माना ।

†**श्री त्यागी :** (देहरादून) : उस तिथि को लद्दाख और काश्मीर भी हमारे पास नहीं थे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे खेद है कि मैं अपनी बात को समझा नहीं पाया जो मुझे बिल्कुल साफ प्रकट होती है । यदि दो देश सीमांत के बारे में एक दूसरे के निर्वचन को चुनौती देते हैं, तो चाहे चेतावनी छोटी ही हो, यह चेतावनी होती है और इसका फैसला व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा या बातचीत या मध्यस्थनिर्णय एवं युद्ध के द्वारा ही होता है और कोई मार्ग नहीं होता । काश्मीर के एक माननीय सदस्य ने लद्दाख के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं । संभवतः उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन को काश्मीर सीमा और लद्दाख के बारे में कुछ पता है, किन्तु मैं उसमें नहीं पड़ रहा ।

मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि हम आप से बात करेंगे, जब आप पूरी तरह पराजित हो जायेंगे, तब हम आप से अपनी शर्तें मनायेंगे ? यह व्यवहारिक बात नहीं है । आप जो सैनिक कार्रवाई करेंगे उस को राजनैतिक कार्रवाई के साथ मिलाना होगा जिससे आप को अगला कदम उठाने में शक्ति मिलेगी । यदि आप शुरू करते ही अन्तिम कदम उठायें तो आप उस सारे अन्तर को कूद नहीं सकते, और आप गिर जाओगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकोगे । एक पग आगे लक्ष्य करना—बड़े पग का स्पष्टतः वांछनीय होता है, जो बिना कुछ हानि हुए—अपनी स्थिति को मजबूत करता है । हमने बहुत पहले, दो या तीन महीने पहले, ८ सितम्बर, की रेखा का सुझाव देने का फैसला किया था क्यों कि यदि चीनी सरकार ने स्वीकार कर लिया तो इससे यह पता चलेगा कि तब से जो कुछ भी हुआ है वह उनका आक्रमण रहा है । उनके लिए यह स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है और उन्होंने इसे नहीं माना । यह स्पष्ट बात है कि ऐसा करना हमारे लिये राजनीतिक राजनयिक, मनोवैज्ञानिक और सैनिक, दृष्टियों से बहुत लाभदायक होगा । किन्तु हमारे द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

केवल इतना कहने के स्थान पर आपको अवश्य कुछ और अधिक करना चाहिये जो वे नहीं करेंगे—इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं, हो सकता है बाद में वे ऐसा करें—मैं कहता हूं कि हमने जो सुझाव रखा है, और जो कुछ कहा है उसमें पिछले दो महीनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने इसे दोहराया है, मुझे याद नहीं कि अपने पत्रों और वक्तव्यों में कितनी बार दोहराया है जैसा कि माननीय सदस्यों को पता होगा। यह सही तरीका है। इस ने बहुत से तटस्थ देशों पर कुछ प्रभाव डाला है जिनकी बैठक कोलम्बो या अन्यत्र कहीं होने वाली है।

मैंने वैसे ही हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जिक्र किया है। मैंने यह कहा था कि जब कभी इस के लिय समय आएगा, यदि सभा सहमत होगी, तो संभवतः हम इसका विचार करेंगे। इतना विलम्ब या इतना जल्दी होने का कोई प्रश्न नहीं है। न ही विलम्ब हुआ है न ही शीघ्रता की गई है। यह सही समय होगा, जब ऐसा सही समय आएगा? मैं केवल यह कह रहा हूं कि हम आज संसार में स्वीकृत धारणाओं के प्रतिकूल काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि अन्य पक्ष इस से सहमत न हों; यह भिन्न मामला है। किन्तु हमारे लिये यह कहना कि हम ऐसी चीज नहीं भेजेंगे और भेजना स्वीकार नहीं कर सकते, जिसे संसार के अधिकतर देशों द्वारा वैध माना जाना चाहिये।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): आपने कुछ और भी कहा था—यदि हम अपनी ८ सितम्बर की स्थिति को पुनः पा लें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: श्री अणे ठीक कहते हैं। मैंने कहा था कि यह प्रारंभिक है—८ सितम्बर आदि का काम। अन्य बातें इस के बाद होंगी। अर्थात् जब हम प्रश्न के गुण दोष के सम्बन्ध में चर्चा करने लगेंगे।

प्रो० रंगा ने दलाई लामा का उल्लेख किया है। वह पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जो चाहें कह सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। यह सच है कि हमने उनको यहां निष्क्रांत सरकार आरंभ करने की अनुमति या स्वीकृत नहीं दी है और मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल ठीक थे और हम ठीक रहेंगे। हम किसी प्रकार उन के मार्ग में नहीं आते। हम अपने देश में किसी सरकार के स्थापित किये जाने की अनुमति नहीं देंगे। यह अत्यधिक महत्व का राजनीतिक मामला है। यदि वह यहां प्रतिद्वन्दी सरकार आरंभ करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह कई प्रकार से हमारे लिये हानिकारक होगा। इस का यह अर्थ होगा कि हम अपने राज्य क्षेत्र से आक्रमणकर्ता को केवल निकालना ही नहीं चाहते अपितु समूचे तिब्बत को स्वतंत्र कराने का भी वायदा करते हैं। यह बड़ा भारी काम है। यदि यह होता है, तो होता है। किन्तु हमारे लिये इस को अपने ऊपर लेना, इसे करने का झंडा उठाना, बुद्धिमत्ता का काम नहीं होगा। अधिक क्या इससे चीनियों को यह कहने का तर्क मिल जाएगा कि वह हमारे बारे में जो कुछ पहले कहते हैं आरोप लगाते रहे हैं वह सच था।

†**श्री रंगा**: हमारे लिये यह कहना गलत है फिर भी प्रधान मंत्री कह रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मेरे गौहाटी के भाषण का उल्लेख किया था। मुझे इस बात का कोई स्मरण नहीं। मुझ से प्रश्न पूछा गया और मेरा उत्तर था कि मुझे पता नहीं। मैं और क्या कह सकता था। वह समझते हैं कि मेरे पास कोई गुप्त सूचना है और फिर भी मैंने यह

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर दिया। । मुझे इसका पता नहीं। मैंने पहले कभी यह नहीं सुना। निस्सन्देह यह पाकिस्तान और चीन के साथ आसाम के बारे में कोई गुप्त समझौते के बारे में प्रश्न था। मैंने पहले कभी नहीं सुना। अतः मैंने कहा कि मुझे इसका पता नहीं।

मैं समझता हूं कि श्री फ्रैंक एंथनी ने लोगों के सहयोग की भावना का उल्लेख किया। मैं उनसे सहमत हूं। संभव है कि मा० सदस्यों ने हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को जांचा होगा अर्थात् समूचे सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज आंदोलन को एक विशिष्ट ढंग के बदलने का, ताकि हमारे युद्ध कार्य में सहायता मिले। यह शक्तिशाली आंदोलन है, जिसमें सीधे तौर पर कार्यपालिका समिति, पंच, प्रत्येक १० लाख आते हैं। कल्पना करो इसके अन्दर समूचा ग्रामीण भारत आ जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से इसका यदि ३० करोड़ लोगों पर नहीं तो २० करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार वे करते हैं उनको निदेश दे सकते हैं चाहे वह कृषि के काम में हो, या छोटे उद्योगों में या और काम में और स्वयंसेवक खड़े करने आदि में युद्ध कार्य के लिये। यह महान प्रयत्न है, राष्ट्र को अधिकाधिक तैयार करना, जितना कोई अन्य पृथक प्रयत्नों का परिणाम नहीं निकल सकता।

मुझे खेद है कि मैं कुछ उठाई गई बातों का उत्तर नहीं दे सका, किन्तु मुझे आशा है कि मैंने बड़ी बातों का उत्तर दे दिया है और आशा है कि सभा यह स्वीकार करेगी कि छोटे मामलों संबंधी छोटे दृष्टिकोण के संबंध में कुछ अन्तर होने के बावजूद, वास्तव में समूची चर्चा में सभा में बड़े मामलों के बारे में पर्याप्त एकमत पाया गया है। मैं मा० सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और एकमत की भावना व्यक्त की है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रधान मंत्री ने नेफा में हुई पराजयों का एक कारण यह बताया है कि इतने ऊंचे हिमालय पर्वत पर अचानक आक्रमण के लिये सेनायें थीं जो मैदानों के काम करने के लिये थीं। क्या १२ अक्तूबर को, जब उन्होंने चीनियों को नेफा से निकालने का आदेश दिया था, उनको पता नहीं था कि हमारी सेनाओं का अनुभव कैसा था?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ने प्रत्येक रैजिमैंट और बटालियन के रिकार्ड को नहीं देखा था। उदाहरण के लिये लद्दाख में तो सेना थी और जो १४००० फुट पर रहने में अभ्यस्त हो गई थी। किन्तु यहां वे लगभग दो सप्ताह या कम समय से थीं, बल्कि एक सप्ताह या दिन से, जबकि उनको अचानक मुकाबला करना पड़ा। वे अभ्स्यत नहीं हुये थे। मैंने केवल एक कारण बताया—किसी बात का समर्थन नहीं किया, जिस का कुछ समय के लिये लोगों पर प्रभाव पड़ा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री प्र० के० देव तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा रखा गया संशोधन संख्या १ सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ संशोधन संख्या ३ भी सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपना संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये, क्योंकि यह प्रधान मंत्री के विचारों के अनुसार है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे खेद है कि मेरे कागजों में, यह संशोधन नहीं है। संशोधन में मूलतः कोई खराबी नहीं है, किन्तु मैं श्री विद्याचरण शुक्ल का संशोधन स्वीकार करूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का संशोधन संख्या ५ सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ। संशोधन संख्या ६ भी मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री विद्याचरण शुक्ल का संशोधन संख्या ९ रखा जाता है। प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न रखा जाये :—

> "यह सभा चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा सम्बन्धी स्थिति पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा इसका मुकाबला करने के लिये अपनाये गये उपायों और नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री अ० सिं० सहगल का संशोधन संख्या १० अब प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभा ने स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९६२/२० अग्रहायण, १८८४ (शक) के बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १० दिसम्बर, १९६२

१९ अग्रहायण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१०	एयर इंडिया बोइंग ७०७ की दुर्घटना . .	२०५९–६०
११	कपड़ा मिलों में कपड़े का स्टाक जमा हो जाना .	२०६०–६१
१२	आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक .	२०६२–६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०६३–६४

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय, अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६२ (भाग २) की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३२१९ में प्रकाशित कपड़ा मशीनरी (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के कार्यवाही सारांश

तीसरे सत्र के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०६४

सचिव ने ३ दिसम्बर, १९६२ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक पटल पर रखे गये :

(१) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६२

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६२

सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव २०६४–२१०२

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा संबंधी स्थिति के बारे में प्रस्ताव किया। प्रस्ताव पर सात स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। प्रधान मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वश्री प्र० के० देव, शिवमूर्ति स्वामी तथा सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुये। श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया। सरदार अ० सिं० सहगल द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव अवरुद्ध हो गया। श्री राम सेवक यादव द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव पर सभा में मतदान हुआ। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री विद्या चरण शुक्ल द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९६२ / २० अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा। केन्द्रीय शिशिक्षुता नियम, १९६२, और शिशिक्षुता नियम, १९६२ में रूपभेद करने के बारे में प्रस्ताव तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में प्रस्ताव।

GMGIPND—LS III—2426 (Ai) LSD—11-1-63—140